दूसरों के जिन दुर्गुणों की आप चर्चा करते हैं उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाने का संकल्प आप ले सकते हैं?-महास्थविर शांति मुनि

जयपुर ▪ दिल्ली से प्रकाशित

बिज़नेस रेमेडीज

वर्ष : 11 | अंक : 203 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए स्वीकृत व्यापार एवं विकास की आवाज मूल्य : 3 रुपए | पेज : 8 दैनिक www.businessremedies.com

जयपुर। सोमवार 5 अगस्त, 2024

भारत का लौह अयस्क उत्पादन जून तिमाही में 9.7 प्रतिशत बढ़ा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। देश का लौह अयस्क उत्पादन

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 9.7 प्रतिशत बढ़कर 7.9 करोड़ टन हो गया है। सरकार ने कहा कि अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लौह अयस्क उत्पादन पिछले साल की समान तिमाही में 7.2 करोड़ टन था। खान मंत्रालय ने बयान में कहा कि चूना पत्थर का उत्पादन 2024-25 की पहली तिमाही में 1.8 प्रतिशत बढ़कर 11.6 करोड़ टन हो गया, जो 2023-24 की अप्रैल-जून अवधि में 11.4 करोड़ टन था। चालू वित्त वर्ष (2024-25) की अप्रैल-जून अवधि में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 11 प्रतिशत बढ़कर 10 लाख टन हो गया है। मंत्रालय ने कहा, 'देश में लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रमुख खनिजों का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड उत्पादन स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में इनके उत्पादन में मजबूत वृद्धि जारी रही है।' अलौह धातु क्षेत्र में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन 1.2 प्रतिशत बढ़कर 10.43 लाख टन हो गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 10.28 लाख टन था। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक तथा चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।

देश में कोयला उत्पादन जुलाई में 6.69 प्रतिशत बढ़कर 7 .41 करोड़ टन रहा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। देश में कोयला उत्पादन जुलाई महीने में 6.69 प्रतिशत बढ़कर 7.41 करोड़ टन रहा।

कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा कि पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में देश में कोयला उत्पादन 6.94 करोड़ टन रहा था। कुल कोयला आपूर्ति इस साल जुलाई में 4.58 प्रतिशत बढ़कर 7.95 करोड़ टन रही जो पिछले साल इसी महीने में 7.60 करोड़ टन थी। मंत्रालय ने एक अलग बयान में कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 10 कोयला खदानों के लिए आदेश जारी किये गये हैं। ये खदान देश की कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।इसमें एक पूरी तरह से खोजी गई और नौ आंशिक रूप से खोजी गई खदानें शामिल हैं। ये खदानें झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देंगी।कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सफल बोलीदाताओं से कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर गौर करने का आग्रह किया।

एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा...

खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव बाजार से हतोत्साहित करने से बैंक जमा बढ़ाने में मदद मिलेगी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव बाजार में दांव से हतोत्साहित करने वाले नियामकीय कदमों से बैंकिंग प्रणाली को बेहद जरूरी जमा जुटाने में मदद मिल सकती है। खारा ने कहा कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर बदलाव जैसी बजट घोषणाओं से जमा वृद्धि के नजरिये से ज्यादा फायदा नहीं होगा।

खारा ने कहा, ''नियामक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए एफएंडओ (वायदा और विकल्प) जैसी चीजों को हतोत्साहित किया जा रहा है। जो लोग इस तरह के साधन का सहारा ले रहे हैं, वे बैंकिंग प्रणाली में वापस आ सकते हैं।'' यह ध्यान देने योग्य है कि कि डेरिवेटिव कारोबार में 90 प्रतिशत निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यह आशंका पैदा हो रही है कि परिवारों की बचत उत्पादक उद्देश्यों में लगने के बजाय 'सट्टेबाजी' में उड़ रही है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, अकेले वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा निवेशकों को ऐसी गतिविधियों में 52,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसपर अंकुश लगाने की जरूरत है। सेबी ऐसे दांव पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सात सूत्रीय योजना लेकर आया है, जबकि आम बजट में भी इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों से जमा वृद्धि ऋण में बढ़ोतरी से साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ है। खारा ने कहा कि यह पैसा वैकल्पिक साधनों मसलन पूंजी बाजार में जा रहा है।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक खाता परिवारों की बचत को जमा करने का प्रमुख साधन है और इसपर ब्याज मिलता है। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में भी ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से अधिक थी। वर्तमान में, जमा और ऋण वृद्धि के बीच के अंतर के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जिसके कारण बैंक कर्ज देने में धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो समग्र आर्थिक वृद्धि के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एसबीआई के पास कुल 20 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी है। खारा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में एसबीआई ऋण में 15 प्रतिशत और जमा में आठ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बैंक का प्रयास जमा वृद्धि को 10 प्रतिशत पर पहुंचाने का होगा।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.47 अरब डॉलर घटकर 667.38 अरब डॉलर रहा

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 3.471 अरब डॉलर घटकर 667.386 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी। इससे पहले के सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 4.003 अरब डॉलर बढ़कर 670.386 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर चला गया था।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 26 जुलाई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.171 अरब डॉलर घटकर 586.877 अरब डॉलर रह गईं।डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी

मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 2.297 अरब डॉलर घटकर 57.695 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 50 लाख डॉलर घटकर 18.202 अरब डॉलर रह गया। आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 20 लाख डॉलर बढ़कर 4.612 अरब डॉलर हो गई।

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र ने दरें कम करके परिपक्वता का प्रदर्शन किया: एमएफआईएन

बिजनेस रेमेडीज/कोलकाता। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के स्व-नियामक संगठन माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (एमएफआईएन) ने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। इनमें से कई ने पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरों में कमी की है। बयान में कहा गया, ब्याज दरों में 150 आधार अंकों तक की कटौती की गई है। एमएफआईएन ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म वित्त) इकाइयां अपने ग्राहकों को लाभ देने में सक्षम रही हैं, जो बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाने और वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने से संभव हुआ है। एमएफआईएन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं निदेशक आलोक मिश्रा ने कहा कि ये स्वैच्छिक कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों तथा उद्योग आचार संहिता से परे हैं। यह जिम्मेदार ऋण प्रथाओं के प्रति क्षेत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

'आत्मनिर्भर' पर जोर से अकुशल आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए: पूर्व गवर्नर सी रंगराजन

बिजनेस रेमेडीज/हैदराबाद। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई देशों ने 'महत्वपूर्ण आयात' के संबंध में आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया।

उन्होंने आगे कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 'आत्मनिर्भर' पर जोर से अकुशल 'आयात प्रतिस्थापन' को बढ़ावा न मिले। सरल शब्दों में आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयातित वस्तुओं को घरेलू उत्पादों से बदलना है। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। रंगराजन ने कहा कि निवेश दर बढ़ाकर, कृषि, विनिर्माण और सेवाओं पर जोर देकर, नई तकनीकों को आत्मसात करके और रोजगार के अनुकूल क्षेत्रों के मिश्रण को बढ़ावा देकर वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ना निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन नई प्रौद्योगिकियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वृद्धि के बिना रोजगार सृजन भी उतना ही बुरा है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे कठिन चुनौती होने जा रहा है। उनके अनुसार हालांकि भारत को अपनी उपलब्धियों को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है, और उच्च शिक्षा को मजबूत करना चाहिए।

भारत में विकास रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु कृषि: नीति आयोग सदस्य रमेश चंद

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। भारत में कृषि विकास रणनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और देश ने 2016-17 से 2022-23 तक के सात वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में पांच प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर हासिल की है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने यह बात कही।

कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) को संबोधित करते हुए रमेश चंद ने कहा कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया में कृषि जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर हासिल की है। उन्होंने कहा, 'भारत में कृषि विकास रणनीति का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है और देश ने 2016-17 से 2022-23 तक की सात वर्ष की अवधि के दौरान ऐतिहासिक रूप से पांच प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर हासिल की है।'

कृषि अर्थशास्त्री ने बताया कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का हिस्सा 2006 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 4.3 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 15 वर्षों में कृषि वृद्धि ने कई देशों को आर्थिक पतन से बचाया है। कृषि से श्रम शक्ति को बाहर निकालने में उद्योग के खराब प्रयासों के कारण, बड़े कार्यबल के लिए लाभकारी रोजगार का दायित्व अभी भी कृषि पर बना हुआ है।' उनके अनुसार, कृषि में हाल की उपलब्धियां और अवसर भारत और विश्व के भविष्य के विकास में कृषि की और भी बड़ी भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। चंद ने कहा कि इन सभी चुनौतियों के कारण आर्थिक और मानव विकास में कृषि की भूमिका को नए सिरे से समझना तथा सभी स्तरों पर कृषि पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया है।

देश में 95 प्रतिशत गांवों के पास है इंटरनेट की सुविधा : संचार मंत्रालय

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली (आईएएनएस)। 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत देश के 95 प्रतिशत गांवों में मौजूदा समय में 3जी या 4जी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। संचार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत में कुल 95.44 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर (मार्च 2024) हैं। इसमें से 39.83 करोड़ यूजर्स ग्रामीण भारत में हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा कि देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 6,12,952 गांवों (अप्रैल 2024) में 3जी/4जी मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। ऐसे में देश के 95.15 प्रतिशत गांवों में

इंटरनेट की सुविधा है।'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत सरकार ने मेट्रो, टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़ने के साथ ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों को जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या पिछले एक दशक में 25.15 करोड़ से बढ़कर 95.44 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें सालाना आधार पर 14.26 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में टेलीकॉम नेटवर्क का देश के सभी कोनों में विस्तार किया गया है। इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ देश के अंदरूनी इलाके भी शामिल हैं।

सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा देने के लिए 'भारतनेट' प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना था। सरकार ने बताया कि 2.2 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.13 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट से जोड़ा जा चुका है। सरकार की ओर से अगस्त 2022 में बॉर्डर एरिया में मोबाइल टावर लगाने के नियमों में बदलाव कर दिया गया था, जिससे कि मोबाइल इंटरनेट सुविधा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।

एफडीआई आकर्षित करने के लिए रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता: जीटीआरआई

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। वैश्विक निवेशकों को भारत की ओर अधिक आकर्षित करने के लिए रणनीतिक सुधारों की जरूरत है, क्योंकि प्रचुर संभावनाएं होने के बावजूद एफडीआई आंकड़े दर्शाते हैं कि देश ने अपने अवसरों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने यह बात कही।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने चार-चरणीय योजना का सुझाव दिया और कहा कि भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक अग्रणी विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद करने वाले उपायों में देश में स्थानांतरित होने वाली कंपनियों के लिए लागत संबंधी नुकसान को कम करना, समूचे कारोबारी चक्र में व्यापार सुगमता में सुधार करना और निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना शामिल है।

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 44.4 अरब अमेरीकी डॉलर का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित किया, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.1 प्रतिशत है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि विश्व विकास रिपोर्ट 2023 में उल्लेख है कि देश चीन (189.1 अरब अमेरीकी डॉलर), ब्राजील (86.1 अरब अमेरीकी डॉलर), ऑस्ट्रेलिया (61.6 अरब अमेरीकी डॉलर) और कनाडा (52.6 अरब अमेरीकी डॉलर) जैसे देशों से काफी पीछे है।

भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 44.4 अरब अमेरीकी डॉलर का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आकर्षित किया, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.1 प्रतिशत है।

जीटीआरआई ने सुझाव दिया गया कि भारत को चीन से स्थानांतरित होने वाले या वैकल्पिक उत्पादन स्थानों पर विचार करने वाले व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी लागत संरचना की पेशकश करनी चाहिए। इसके लिए भारत को चार लागत-संबंधी घटकों श्रम, दर सामग्री, ऊर्जा और वित्तीय लागत पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक शोध संस्थान के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, 'भारत में आयात पर निर्भरता और उच्च शुल्क के कारण गैर-पारंपरिक उत्पादनों के लिए कच्चे माल की लागत अधिक है। चीन को बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादन तथा कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण कम लागत का लाभ मिलता है, जबकि वियतनाम आयात पर कम या शून्य शुल्क के साथ प्रतिस्पर्धी लागत प्रदान करता है।'' उन्होंने कहा कि भारत में वित्तीय लागत सबसे अधिक है, जहां ऋण दरें करीब नौ से 10 प्रतिशत हैं, जबकि चीन में ब्याज दरें चार से पांच प्रतिशत के आसपास हैं। वियतनाम में दरें करीब सात से आठ प्रतिशत हैं। श्रीवास्तव ने कहा, ''भारत को इन लागतों पर ध्यान देने तथा सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प बनने का प्रयास करने की जरूरत है।''

बिजली की खपत जुलाई में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 145.40 अरब यूनिट रही

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। जुलाई में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद देश में बिजली की खपत पर असर पड़ा है और यह सालाना आधार पर सिर्फ 3.5 प्रतिशत बढ़कर 145.40 अरब यूनिट रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई, 2023 में देश की बिजली खपत 140.41 अरब यूनिट रही थी। एक दिन में बिजली की सर्वाधिक मांग पिछले महीने बढ़कर 226.63 गीगावाट हो गई जबकि एक साल पहले समान महीने में यह 208.95 गीगावाट थी। एक दिन में बिजली की सर्वाधिक मांग ने इस साल मई में रिकॉर्ड बनाया था। भीषण गर्मी के दौर में एक दिन की सर्वाधिक बिजली मांग 250.20 गीगावाट रही थी। पिछला रिकॉर्ड सितंबर, 2023 में 243.27 गीगावाट का था। इस साल की शुरुआत में बिजली मंत्रालय ने मई में दिन के समय 235 गीगावाट और शाम के समय 225 गीगावाट की बिजली मांग रहने का अनुमान जताया था। वहीं जून, 2024 के लिए यह अनुमान दिन के समय 240 गीगावाट और शाम के समय 235 गीगावाट का था। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा था कि इस साल गर्मियों में अधिकतम बिजली की मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है। हालांकि, देश में मानसून की शुरुआत के साथ, उपभोक्ताओं को चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिली। इससे एयर कंडीशनर और बड़े कूलर जैसे उपकरणों के इस्तेमाल की कम जरूरत पड़ी। इससे देश में बिजली की खपत में कमी आई

हालांकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि मानसून के समय अधिक नमी होने से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है लिहाजा आने वाले दिनों में बिजली की मांग और खपत स्थिर रहेगी।

न्यूज ब्रीफ

सिल्क एक्सपो और हैंडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी शुरू

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर। जयपुर में जवाहर कला केंद्र में उमंग सिल्क एक्सपो की शुरुआत हुई । इसमें देशभर के 20 राज्यों से आए दुकानदारों ने 150 से ज्यादा साड़ियों के स्टाल लगाए हैं। यहां एक छत के नीचे कई राज्यों में पहने जाने वाली अलग-अलग वैरायटी की साड़ियां लोगों को खूब भा रही हैं। सिल्क एक्सपो और हैंडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी का उद्घाटन आज जयपुर की सांसद महोदया मंजू शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। यह प्रदर्शनी 4 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी । यहां विशेष रूप से सिल्क की डिजाइनर साड़ियां खरीदी के लिए उपलब्ध हैं। सांसद मंजू शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के लिए आवंटन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 171 करोड़ रुपया से बढ़कर 236 करोड़ रुपये हो गया है यह बढ़ी हुई धनराशि कारीगरों के कौशल को ब?ाने और उनकी बाजार पहुँच में सुधार लाने और पारंपरिक हस्तशिल्प में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी। आयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि मार्केट में बहुत-सी ऐसी साड़ियां मिल रही हैं जो देखने में तो आकर्षक हैं, पर पहनने पर स्किन संबंधी समस्याओं को बढ़ा देती है, ऐसे में हम आर्गेनिक साड़ियां लेकर जयपुर आये है, जिनसे स्किन एलर्जी नहीं होती है। एक्सपो में आर्गेनिक साड़ियां भी हैं, जो फूलों के रस, जड़ी-बूटियों, केसर, दूध, चंदन से मिलकर बनाई गई हैं। इस कारण यह साड़ी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां साड़ियों की अनेक वैरायटी हैं, जिनमें मूंगा सिल्क, सिल्क, कांजीवरम, पैठणी, कढ़वा बूटी, तनछुई शामिल हैं।

प्रदेश में 100 एनीकटों का निर्माण, मरम्मकत एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा : जल संसाधन मंत्री

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में 100 एनीकटों के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। जिसके तहत नानोर-झालावाड में सौर आधारित फव्वारा सिंचाई प्रणाली कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निविदा आंमत्रित कर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले विधायक सुरेश गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि झालावाड जिले के बकानी क्षेत्र में राजपुरा लघु सिंचाई परियोजना संचालित है, जिसके द्वारा 310 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजपुरा लघु सिंचाई परियोजना के विकास के लिये विगत 3 वर्षो में मनरेगा के अन्तर्गत दो कार्य करवाये गये, जिसका विवरण उन्होंने रखा।

स्पीकर हैल्प डेस्क का शुभारंभ

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में अब डॉक्टरों की जानकारी के लिए मरीज व परिजनों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष हैल्प डेस्क पर मरीजों को एक ही जगह समस्त जानकारी मिल जाएगी। आपातकालीन ईकाई के पास इस हैल्प डेस्क की स्थापना की गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में स्पीकर हैल्प डेस्क का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लम्बे समय से अस्पताल में यह जानकारी मिल रही थी कि सही जानकारी के अभाव में मरीज व उनके परिजनों को यहां-वहां भटकना प?ता है। उन्हें बीमारी बताने के बाद भी सही डॉक्टर, विभाग, कमरा नम्बर, दवा केन्द्र, जांच केन्द्र, ऑपरेशन थियेटर, ओपीडी व इंडोर पेशेंट से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती है। उनका काफी समय खराब हो जाता है। देवनानी ने बताया कि मरीज व उनके परिजनों की सुविधा के लिए अस्पताल की आपातकालीन ईकाई के पास अधीक्षक कक्ष से पहले हैल्प डेस्क की स्थापना की गई है। यहां 24 घण्टे तीन पारियों में स्टाफ तैनात रहेगा। कोई भी मरीज या उनका परिजन आकर यहां चिकित्सा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है।

भारत दलहन सेमिनार 9 अगस्त को दिल्ली में*

बिज़नेस रेमेडीज/बीकानेर। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन बीकानेर एवं इंडिया पल्सेज ग्रेन एसोसिएशन मुम्बई के संयुक्त तत्वावधान में परिचर्चा का आयोजन बीकानेर जिला उद्योग संघ के राउंड टेबल सभागार में हुई। इंडिया ग्रेन पल्सेज एसोसिएशन के संगठन मंत्री सतीश उपाध्याय ने बताया कि 9 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पूरे भारतवर्ष के दाल मिलर्स एवं दलहन व्यापारी इस सेमिनार में शामिल होंगे तथा दाल दलहन व्यापार की समस्याओं के समाधान सुझाव एवं नई तकनीक पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर जयकिशन अग्रवाल ने दाल मिलर्स के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण पर अपने सुझाव रखे। दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरसिंहदास मीमानी ने सतीश उपाध्याय को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया । सचिव राजकुमार पचीसिया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया । संजय पेड़ीवाल ने सभी दाल मिलर्स से दिल्ली में आयोजित होने वाली सेमिनार में अधिक से अधिक पहुंचने की अपील की।

राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान, पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य बजट में दी गई ढेरों सौगातें : मुख्यमंत्री शर्मा

बजट सौगातों के लिए देवासी समाज के प्रतिनिधियों ने जताया आभार

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाएं एवं उम्मीदें इस बजट से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि किसान, पशुपालक, युवा, महिला सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर सिरोही एवं बाली सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए धन्यवाद देने आए देवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के सभी वादों को हमारी सरकार पूरा कर रही है।

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का किया जाएगा गठन : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालकों का अहम योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में पशुपालकों के सशक्तिकरण के लिए ढेरों सौगातें दी गई हैं। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुधारू पशुओं के नस्ल विकास एवं नर गौवंश की समस्या के समाधान के लिए अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की जाएगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों के सृजन, ग्राम पंचायतों में इस वर्ष 500 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने सहित विभिन्न घोषणाएं राज्य बजट में की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में

चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा एवं पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

दुग्ध उत्पादकों के लिए किया जाएगा सुविधाओं का विस्तार : शर्मा ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटस का सुदृढ़ीकरण, 95 करोड़ रुपये की लागत से पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट तथा 25 करोड़ रुपये से कोटा में केटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जाएंगे। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाएंगे, 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां तथा किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने हेतु 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोले जायेंगे।

बुनियादी ढांचे का तेजी से हो रहा सुदृढ़ीकरण : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण के लिए भी राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट में 18.90 करोड़ रुपये की लागत से रानी, बाली, फालना तथा 50 गांवों हेतु पेयजल (पाली) आपूर्ति व पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है। साथ ही, बाली विधानसभा क्षेत्र में 176 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य करवाए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि 15.50 करोड़ रुपये की लागत से फुटिया बांध (बाली)-पाली के जीर्णोद्वार एवं बांध की ऊँचाई बढ़ाये जाने सम्बन्धी कार्य कराएंगे। उन्होंने कहा कि बाली में देवनारायण आवासीय विद्यालय की स्थापना, बाली उपजिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, साण्डेराव, देसूरी-पाली में नये ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, सादड़ी-पाली में फल-फूल मण्डी स्थापित करने, बाली में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं बाली में खेल स्टेडियम की स्थापना जैसी अहम घोषणाएं बजट में की गई हैं। इस दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, जालोर-सिरोही सांसदी लुम्बाराम चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, समाराम एवं गोपीचंद मीणा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुए

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया। बागडे राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मेलन में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'एक वृक्ष मां के नाम' और प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क, राज्यपालों की भूमिका और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपालों की भूमिका जैसे विषयों के विभिन्न सत्रों में शामिल हुए।

स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्राथमिक कक्षा भवन का लोकार्पण

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल माकड़वाली के प्राथमिक कक्षा भवन के लोकार्पण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाने का आह्वान किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल माकड़वाली श्री नगर ब्लॉक के प्राथमिक कक्षाओं के भवन का लोकार्पण किया। समारोह में स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यार्थियों ने कलस्तर स्तरीय पुरस्कार वितरण भी किए गए। इस अवसर पर

आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई बोर्ड से ग्रामीण बच्चों को अध्ययन करवाने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल आरम्भ करने के लिए संकल्पना की गई थी। अब इसमें कक्षा 5 तक के विद्यार्थी भी अध्ययन करेंगे। इससे स्वस्थ और आनन्दायक वातावरण में पढ़ने का बचपन से ही अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवाओं तथा विद्यार्थियों के लिए आदर्श रहे हैं। इनकी जीवनी का प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम के संस्कार पैदा होंगे। यह पीढ़ी ही भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सर्वाधिक योगदान प्रदान करेगी। स्वामी विवेकानन्द ने सनातन संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचाया था। भारत विश्व गुरू है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों का अभिभावक बनकर शिक्षा प्रदान करने से अच्छे परिणाम आते हैं। योग की धूम विश्व में होने लगी है। विद्यालयों की प्रार्थना सभा में योग भी करवाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के विद्यार्थी वैश्विक जगत की प्रतिस्पर्धाओं में टिक पाएंगे। इस दृष्टि से विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है। बच्चों को सुसंस्कृत नागरिक बनाने की जिम्मेदारी विद्यालय, अभिभावक तथा समाज सभी की है। मूल्यपरक शिक्षा समाज को नई दिशा देती है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से राजकीय विद्यालयों की प्रतिष्ठा तथा स्वीकार्यता की पुर्नस्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी उच्च स्तरीय अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय खोले गए थे। उस समय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए इसे प्राथमिक स्तर से आरम्भ करने की संकल्पना की गई थी। इसे आज पूर्ण रूप से होता देखकर अच्छा लग रहा है। वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा आरम्भ करवाना सराहनीय है। इस विद्यालय का शुभारम्भ केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा किया गया था।

सांसद भूपेन्द्र यादव ने राज्य के बजट को सड़क, बिजली-पानी की समस्याओं को दूर करने वाला बजट बताया

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

अलवर के सांसद और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रीभूपेन्द्र यादव शनिवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले के दौरे पर रहे उन्होंने मांढन स्थित सिद्ध सेवा धाम में शिव पूजा की।

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने मांढन के लोगों का लोकसभा चुनाव में सहयोग देने के लिए आभार जताया। उन्होंने मांढन को नगर पालिका बनाने और यहा पर आधारभुत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का भी आभार जताया। उन्होंने बताया कि देश बजट में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने को लेकर भी जोर दिया है और कहा की यह उनकी आजीविका का विषय होना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बैठक होनी चाहिए। भूपेन्द्र यादव ने कहा की जो भी पंचायत महिलाओ के सेल्फ हेल्प

ग्रुप के लिए हॉल की सुविधा चाहती हैं उन्हे वह उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने स्पोर्ट्स के माध्यम से Fit India को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा की मंदिरों के साथ-साथ खेल के मैदान बनाये जाना भी जरूरी है।

भूपेन्द्र यादव ने गंडाला में पक्षीघर का उद्घाटन किया साथ ही सभी लोगों से एक पेरू माँ के नाम अभियान से जुडने की अपील की और कहा की हम अपने जीवन में कम से कम एक पेरू जरूर लगाए। उन्होंने यह भी कहा की आज भी हम पूरी तरह से हमारी सारी जरूरतों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर हैं। उन्होंने पीपल, नीम, बहेड़ा, आमला और जामुन जैसे देसी पेड़ लगाने की भी अपील की। उन्होंने कहा की प्रकृति हमें हमारे जीवन में सब कुछ देती है और ये हमारी जिम्मेदारी है की हम भी प्रकृति को वापस दें। भूपेन्द्र यादव ने गंडाला के लोगों से उनकी झील को भी सबसे साफ झील बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। भूपेन्द्र यादव ने क्षेत्र के पानी, सड़क और पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी के कार्यों को प्रशासन के साथ बात करके पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने गंडाला में ई-लाइब्रेरी, महिलाओ के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाने में भी सांसद के नाते सहयोग करने की बात कही। केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री रेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल का भी पेयजल के लिए ERCP के तहत बुचारा बाँध तक पानी लाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और कहा की यमुना के पानी के लिए भी हरियाणा की सरकार से सकारात्मक बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा की केन्द्र सरकार स्किल डेवलपमेंट का बजट लेकर आई है और राजस्थान सरकार ने भी सडक, बिजली और पानी की समस्याओ को दूर करने वाला बजट पास किया है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि वह बड़ी संख्या मे आमजन मौजूद रहे।

केन्द्रीय मंत्री ने सैनी महासभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर में आयोजित सैनी महासभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में कार्यकारिणी के अध्यक्ष पूरण सैनी एवं अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज के प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

केंद्रीय मंत्री यादव ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामना देते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से कार्यकारिणी द्वारा शपथ ली गई है उसी उद्देश्य को पूरी लगन व निष्ठा से निभाकर समाज को आगे बढाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि देश व समाज को नई दिशा देने में जिन महापुरूषों ने कार्य किया उनमें महात्मा ज्योतिराव फूले का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले एवं उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फूले ने समाज के उत्थान, विकास, कुरीतियों को दूर करने व बालिका शिक्षा की दिशा में जो कार्य किए है वह वर्तमान पीढी के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं। वर्तमान पीढी को उनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास व उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनी समाज शिक्षित एवं मेहनतकश समाज है तथा अपनी प्रतिभा और कौशल की बदौलत प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाता रहा है। इस समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है तथा बालिका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जीवन में भोजन, औषधि आदि जीवन व्यतीत करने के लिए प्रदान करती है तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है प्रकृति के सौन्दर्यकरण को बढ़ाने लिए पेड लगाने आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संचालित 'एक पेड मां के नाम अभियान' के तहत प्रत्येक व्यक्ति पौधे लगाए और उनका रखरखाव भी करें।

अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए एसओपी को दिया अंतिम रूप

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने विभिन्न अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स के सुचारू संचालन एवं उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) तैयार की है। इस एसओपी को स्वास्थ्य भवन में आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम रूप दिया गया। यह एसओपी लागू होने से प्रदेश के अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बेहतर संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन संसाधनों की उपलब्धता और प्रभावी प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए थे। उन्होंने अस्पतालों में स्थापित आक्सीजन प्लांट्स के प्रभावी संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने की आवश्यकता व्यक्त की थी। आरएमएससीएल ने विषय विशेषज्ञों, उद्योग विशेषज्ञों, और विभिन्न अस्पताल प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर इस एसओपी का अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। राज्य नोडल अधिकारी (ऑक्सीजन प्रबंधन), डॉ. प्रेम सिंह ने ड्राफ्ट एसओपी में शामिल बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। नेहा गिरि ने बैठक में कहा कि प्लांट्स में प्रेशर अलार्म के साथ ऑक्सीजन शुद्धता अलार्म भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब्स के माध्यम से ऑक्सीजन शुद्धता परीक्षण की आवृत्ति को निर्धारित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एसओपी में अस्पतालों के लिए एक चेकलिस्ट शामिल की गई है, जिसमें यह बताया जाए कि अगर प्लांट्स में कोई समस्या आती है तो कब और किस स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता है। उन्होंने ऑक्सीजन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए ऑक्सीजन संचालन और बीएमई की नियुक्ति और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. सुशील परमार ने एसओपी को तकनीकी और प्लांट ऑपरेटर्स के उपयोग के अनुकूल बनाने और अग्नि सुरक्षा मुद्दों को लेकर सुझाव दिए। पाथ इंटरनेशनल के जयेन्द्र कसार ने कोविड के दौरान ऑक्सीजन प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बड़े अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स का कितना प्रभावी उपयोग हुआ है। एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने प्लांट्स की वर्तमान स्थिति और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में बताया। अधिशाषी अभियंता मुकेश कुशवाहा, डॉ. संदीप कोठारी, और इंडस्ट्री विशेषज्ञ नवीन शर्मा एवं दीक्षा गोसाई ने भी एसओपी के संबंध में अपने सुझाव दिए।

आवश्यकता

बिजनेस रेमेडीज दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें

बिजनेस रेमेडीज

63/118, ढीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर -302020

0141-278568,9929106227

E-Mail: remediesbusiness@gmail.com

businessremedies@yahoo.com

(This is a public announcement for information purposes only and is not a Prospectus announcement) (This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)

RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company in the name of "Rajputana Industries Private Limited" under the provisions of the Companies Act,1956 vide Certificate of Incorporation dated June 13, 2011, issued by Central Registration Centre, Rajasthan bearing Corporate Identification Number U31909RJ2011PTC035485. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company vide shareholders resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on April 21, 2023 and name of company was changed to "Rajputana Industries Limited" pursuant to issuance of Fresh Certification of Incorporation dated May 04, 2023 by Registrar of Companies, Jaipur bearing Corporate Identification Number U31909RJ2011PLC035485. For details of Incorporation, Change of Name and Registered Office of our company, please refer to chapter titled *"Our History and Certain Other Corporate Matters"* beginning on page 173 of Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: F-269-B, Road No. 13, VKIA, Jaipur Rajasthan 302013 India. | **Tel No:** +91 9588841031| **Email:** cs@rajputanaindustries.com| Website: www.rajputanaindustries.com
Contact Person: Sonal Jain, Company Secretary and Compliance Officer | **CIN:** U31909RJ2011PLC035485

PROMOTERS OF THE COMPANY: SHERA ENERGY LIMITED, ISHA INFRAPOWER PRIVATE LIMITED, MR. SHEIKH NASEEM AND MRS. SHIVANI SHEIKH

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 62,85,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 38 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 28 PER EQUITY SHARE), AGGREGATING TO ₹ 2288.30 LAKHS ("THE ISSUE"). THIS ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 3,60,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 136.80 LAKHS (CONSTITUTING 1.62% OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION") 30,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 11.40 LAKHS (CONSTITUTING 0.14% OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION") AND 3,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 114 LAKHS (CONSTITUTING 1.35% OF THE POST-ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS ("THE SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION, EMPLOYEE RESERVATION PORTION AND SHERA ENERGY LIMITED SHAREHOLDERS RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.29% AND 25.19% RESPECTIVELY OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: ₹ 38/- PER EQUITY SHARE AND THE FACE VALUE IS ₹ 10/- EACH
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 38/- PER EQUITY SHARE

THE ISSUE PRICE IS 3.80 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

BID/ISSUE PERIOD
BID/ISSUE OPENED ON TUESDAY, JULY 30, 2024
BID/ISSUE CLOSED ON THURSDAY, AUGUST 01, 2024

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein Not More than 50.00% of the Net Issue was made available for allocation to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**", the "**QIB Portion**"), provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations **("Anchor Investor Portion"),** of which one third shall be reserved for domestic mutual funds subject to valid bids received from domestic mutual funds on or above the Anchor Investor allocation price. Further, 5.00% of the Net QIB portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual funds subject to valid Bids received on or above the Issue Price. Further, Not Less than 15.00% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and Not Less than 35.00% of the Net Issue was made available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilise the Applications Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing the details of their respective bank accounts (including UPI ID for RIBs using UPI mechanism), in which the corresponding Bid Amounts were blocked by SCSBs or Sponsor Bank, as applicable. For details, please refer chapter titled ***"Issue Procedure"*** beginning on page **338** of the Red Herring Prospectus. The Investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to NSE Limited. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited. The trading is proposed to be commenced on or about **Tuesday, August 06, 2024** *.

*Please read this line **"Underwriting Agreement dated September 29, 2023, entered into between our Company and the Underwriters"** of the chapter **"Material Contracts and Documents for Inspection"** of our DRHP, RHP and Prospectus as **"Underwriting Agreement dated September 29, 2023, entered into between our Company, the Registrar to the Issue and the Underwriters"**.*

*Subject to the receipt of Listing and Trading approval from NSE EMERGE Platform.

The bidding period for Anchor Investors opened and closed on Monday, **July 29, 2024**. The Company received 2 Anchor Investor Applications for **18,78,000** Equity Shares. The Anchor Investor Allocation Price was finalized at **38** per Equity Share. A total of **16,11,000** Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion, aggregating to **₹ 6,12,18,000**.

The Issue has received **371907** applications for **1639980000** Equity shares (Before Technical Rejections, Multiple Rejections, bids not banked and invalid duplicate / Multiple bids) including Market Maker Application of **3,60,000** Equity Shares and excluding Anchor Investor Application. The Issue was subscribed to the extent of **392.75** times (excluding Anchor investor portion) as per the application data (Before Technical Rejections, Multiple Rejections, bids not banked and after removing invalid duplicate / Multiple bids). After considering the technical rejections cases, the Issue was subscribed **345.78** times (excluding Anchor investor portion).

The details of application received (Before Technical Rejection but after bids not banked).

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares applied	No. of Equity Shares reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (In ₹)
Market Maker	1	360000	360000	1	13680000.00
Eligible Employees	8	96000	30000	3.20	3648000.00
Eligible Shareholders category	678	2034000	300000	6.78	77634000.00
QIB (excluding Anchor Investor Portion)	73	195021000	1074000	181.58	7410798000.00
Non-Institutional Investors	16419	378285000	900000	420.32	14371149000.00
Retail Individual Investors	354728	1064184000	2010000	529.44	40437063000.00
Total	**371907**	**1639980000**	**4674000**	**350.87**	**62313972000.00**

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds are detailed below: (Technical Rejection)

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares
Market Maker	0	0
Eligible Employees	1	12000
Eligible Shareholders category	17	51000
QIB (excluding Anchor Investor Portion)	1	3984000
Non-Institutional Investors	255	2691000
Retail Individual Investors	5675	17025000
Total	**5949**	**23763000**

Final Demand

A summary of final demand as per National Stock Exchange of India Limited as on the Bid/Issue closing date at different Bid Prices is as under:

Bid Price	Bid Quantity	% Of Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
CUT OFF	771366000	41.747	1843863000	41.747
38.00	1072497000	58.044	1843863000	58.044
37.00	1521000	0.0823	1845384000	0.0823
36.00	2346000	0.1270	1847730000	0.1270

Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited on **02.08.2024.**

1. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off price or at or above the Issue Price of ₹ 38/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category was subscribed to the extent of **520.97** times. The Total number of Equity Shares allotted in this category is **2010000** Equity Shares to **670** successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of applications received	% Of Total	Total No. of shares applied in each category	% Of Total	No. of successful applicants	Ratio	Total no. of Shares Allotted
1047159000	349053	100	1047159000	100	670	1:521	2010000
Total	**349053**	**100**	**1047159000**	**100**	**670**	**1:521**	**2010000**

2. Allocation to QIB (excluding Anchor Investor) (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, who have Bid at or above the Issue Price per Equity Share was finalised in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category has been subscribed to the extent of **177.87** times. The Total number of Equity Shares allotted in this category is **1074000** Equity Shares to **72** successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of applications received	% Of Total	Total No. of shares applied in each category	% Of Total	No. of successful applicants	Ratio	Total no. of Shares Allotted
240000	1	1.39	240000	0.13	1	1:1	3000
528000	2	2.78	1056000	0.55	2	1:1	6000
531000	1	1.39	531000	0.28	1	1:1	3000
537000	1	1.39	537000	0.28	1	1:1	3000
540000	1	1.39	540000	0.28	1	1:1	3000
660000	1	1.39	660000	0.35	1	1:1	3000
726000	1	1.39	726000	0.38	1	1:1	3000
780000	2	2.78	1560000	0.82	2	1:1	6000
3000 additional shares are allocated						1:2	3000
921000	1	1.39	921000	0.48	1	1:1	6000
960000	1	1.39	960000	0.50	1	1:1	6000
1023000	1	1.39	1023000	0.54	1	1:1	6000
1074000	1	1.39	1074000	0.56	1	1:1	6000
1185000	1	1.39	1185000	0.62	1	1:1	6000
1287000	1	1.39	1287000	0.67	1	1:1	6000
1317000	1	1.39	1317000	0.69	1	1:1	9000
1320000	1	1.39	1320000	0.69	1	1:1	9000
1581000	1	1.39	1581000	0.83	1	1:1	9000
1800000	1	1.39	1800000	0.94	1	1:1	9000
2133000	1	1.39	2133000	1.12	1	1:1	12000
2208000	1	1.39	2208000	1.16	1	1:1	12000
2214000	1	1.39	2214000	1.16	1	1:1	12000
2217000	1	1.39	2217000	1.16	1	1:1	12000
2220000	10	13.89	22200000	11.62	10	1:1	120000
3000 additional shares are allocated						2:10	6000
2400000	1	1.39	2400000	1.26	1	1:1	15000
2631000	3	4.17	7893000	4.13	3	1:1	45000
2634000	1	1.39	2634000	1.38	1	1:1	15000
3027000	1	1.39	3027000	1.58	1	1:1	18000
3411000	1	1.39	3411000	1.79	1	1:1	18000
3678000	1	1.39	3678000	1.93	1	1:1	21000
3684000	1	1.39	3684000	1.93	1	1:1	21000
3738000	1	1.39	3738000	1.96	1	1:1	21000
3945000	5	6.94	19725000	10.33	5	1:1	105000
3000 additional shares are allocated						2:5	6000
3948000	1	1.39	3948000	2.07	1	1:1	21000
3963000	1	1.39	3963000	2.07	1	1:1	21000
3966000	1	1.39	3966000	2.08	1	1:1	21000
3984000	20	27.78	79680000	41.71	20	1:1	420000
3000 additional shares are allocated						9:20	27000
Total	**72**	**100.00**	**191037000**	**100.00**	**72**		**1074000**

3. Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to Non-Institutional Investors, who have Bid at or above the Issue Price of ₹ 38/- per Equity Share was finalised in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category has been subscribed to the extent of **417.33** times. The Total number of Equity Shares allotted in this category is 900000 Equity Shares to **271** successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated / allotted
6000	10511	65.03	63066000	16.79	50	4:841	150000
9000	1280	7.92	11520000	3.07	9	5:711	27000
12000	1110	6.87	13320000	3.55	11	9:908	33000
15000	511	3.16	7665000	2.04	6	6:511	18000
18000	176	1.09	3168000	0.84	3	3:176	9000
21000	120	0.74	2520000	0.67	2	1:60	6000
24000	201	1.24	4824000	1.28	4	4:201	12000
27000	963	5.96	26001000	6.92	21	7:321	63000
30000	451	2.79	13530000	3.60	11	1:41	33000
33000	99	0.61	3267000	0.87	3	1:33	9000
36000	31	0.19	1116000	0.30	1	1:31	3000
39000	33	0.20	1287000	0.34	1	1:33	3000
42000	28	0.17	1176000	0.31	1	1:28	3000
45000	38	0.24	1710000	0.46	1	1:38	3000
48000	15	0.09	720000	0.19	1	1:15	3000
51000	39	0.24	1989000	0.53	2	2:39	6000
54000	33	0.20	1782000	0.47	1	1:33	3000
60000	66	0.41	3960000	1.05	3	1:22	9000
63000	23	0.14	1449000	0.39	1	1:23	3000
66000	18	0.11	1188000	0.32	1	1:18	3000
72000	8	0.05	576000	0.15	1	1:8	3000
81000	11	0.07	891000	0.24	1	1:11	3000
90000	19	0.12	1710000	0.46	1	1:19	3000
99000	9	0.06	891000	0.24	1	1:9	3000
105000	9	0.06	945000	0.25	1	1:9	3000
108000	8	0.05	864000	0.23	1	1:8	3000
120000	9	0.06	1080000	0.29	1	1:9	3000
132000	21	0.13	2772000	0.74	2	2:21	6000

(Continued on next Page....)

ramaads

(....Continued from previous Page)

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Allocation per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated / allotted
135000	9	0.06	1215000	0.32	1	1:9	3000
150000	11	0.07	1650000	0.44	1	1:11	3000
180000	5	0.03	900000	0.24	1	1:5	3000
210000	5	0.03	1050000	0.28	1	1:5	3000
225000	3	0.02	675000	0.18	1	1:3	3000
240000	3	0.02	720000	0.19	1	1:3	3000
261000	7	0.04	1827000	0.49	2	2:7	6000
264000	33	0.20	8712000	2.32	7	7:33	21000
300000	6	0.04	1800000	0.48	1	1:6	3000
306000	2	0.01	612000	0.16	1	1:2	3000
324000	4	0.02	1296000	0.35	1	1:4	3000
366000	2	0.01	732000	0.19	1	1:2	3000
381000	3	0.02	1143000	0.30	1	1:3	3000
402000	2	0.01	804000	0.21	1	1:2	3000
471000	6	0.04	2826000	0.75	2	1:3	6000
525000	2	0.01	1050000	0.28	1	1:2	3000
528000	2	0.01	1056000	0.28	1	1:2	3000
582000	1	0.01	582000	0.15	1	1:1	3000
594000	1	0.01	594000	0.16	1	1:1	3000
600000	6	0.04	3600000	0.96	3	1:2	9000
606000	1	0.01	606000	0.16	1	1:1	3000
612000	1	0.01	612000	0.16	1	1:1	3000
633000	2	0.01	1266000	0.34	1	1:2	3000
639000	1	0.01	639000	0.17	1	1:1	3000
654000	1	0.01	654000	0.17	1	1:1	3000
657000	2	0.01	1314000	0.35	1	1:2	3000
660000	1	0.01	660000	0.18	1	1:1	3000
690000	1	0.01	690000	0.18	1	1:1	3000
702000	1	0.01	702000	0.19	1	1:1	3000
705000	1	0.01	705000	0.19	1	1:1	3000
717000	1	0.01	717000	0.19	1	1:1	3000
750000	3	0.02	2250000	0.60	2	2:3	6000
765000	1	0.01	765000	0.20	1	1:1	3000
768000	1	0.01	768000	0.20	1	1:1	3000
789000	1	0.01	789000	0.21	1	1:1	3000
792000	1	0.01	792000	0.21	1	1:1	3000
813000	1	0.01	813000	0.22	1	1:1	3000
819000	1	0.01	819000	0.22	1	1:1	3000
825000	1	0.01	825000	0.22	1	1:1	3000
855000	2	0.01	1710000	0.46	1	1:2	3000
900000	6	0.04	5400000	1.44	4	2:3	12000
945000	1	0.01	945000	0.25	1	1:1	3000
969000	1	0.01	969000	0.26	1	1:1	3000
975000	1	0.01	975000	0.26	1	1:1	3000
984000	1	0.01	984000	0.26	1	1:1	3000
990000	1	0.01	990000	0.26	1	1:1	3000
1002000	1	0.01	1002000	0.27	1	1:1	3000
1023000	1	0.01	1023000	0.27	1	1:1	3000
1050000	1	0.01	1050000	0.28	1	1:1	3000
1056000	1	0.01	1056000	0.28	1	1:1	3000
1086000	1	0.01	1086000	0.29	1	1:1	3000
1089000	2	0.01	2178000	0.58	2	1:1	6000
1101000	1	0.01	1101000	0.29	1	1:1	3000
1116000	1	0.01	1116000	0.30	1	1:1	3000
1131000	2	0.01	2262000	0.60	2	1:1	6000
1146000	1	0.01	1146000	0.31	1	1:1	3000
1158000	1	0.01	1158000	0.31	1	1:1	3000
1182000	1	0.01	1182000	0.31	1	1:1	3000
1209000	2	0.01	2418000	0.64	2	1:1	6000
1230000	1	0.01	1230000	0.33	1	1:1	3000
1242000	1	0.01	1242000	0.33	1	1:1	3000
1245000	1	0.01	1245000	0.33	1	1:1	3000
1272000	1	0.01	1272000	0.34	1	1:1	3000
1275000	1	0.01	1275000	0.34	1	1:1	3000
1314000	1	0.01	1314000	0.35	1	1:1	3000
1317000	4	0.02	5268000	1.40	4	1:1	12000
1335000	2	0.01	2670000	0.71	2	1:1	6000
1350000	1	0.01	1350000	0.36	1	1:1	3000
1353000	1	0.01	1353000	0.36	1	1:1	3000
1377000	2	0.01	2754000	0.73	2	1:1	6000
1407000	1	0.01	1407000	0.37	1	1:1	3000
1440000	1	0.01	1440000	0.38	1	1:1	3000
1455000	1	0.01	1455000	0.39	1	1:1	3000
1482000	1	0.01	1482000	0.39	1	1:1	3000
1488000	1	0.01	1488000	0.40	1	1:1	3000
1350000	1	0.01	1350000	0.36	1	1:1	3000
1353000	1	0.01	1353000	0.36	1	1:1	3000
1377000	2	0.01	2754000	0.73	2	1:1	6000
1407000	1	0.01	1407000	0.37	1	1:1	3000
1440000	1	0.01	1440000	0.38	1	1:1	3000
1455000	1	0.01	1455000	0.39	1	1:1	3000
1482000	1	0.01	1482000	0.39	1	1:1	3000
1488000	1	0.01	1488000	0.40	1	1:1	3000
1491000	1	0.01	1491000	0.40	1	1:1	3000
1500000	2	0.01	3000000	0.80	2	1:1	6000
1578000	1	0.01	1578000	0.42	1	1:1	3000
1581000	1	0.01	1581000	0.42	1	1:1	3000
1590000	1	0.01	1590000	0.42	1	1:1	3000
1710000	2	0.01	3420000	0.91	2	1:1	6000
3000 additional shares are allocated						1:2	3000
1857000	1	0.01	1857000	0.49	1	1:1	6000
2142000	1	0.01	2142000	0.57	1	1:1	6000
2250000	1	0.01	2250000	0.60	1	1:1	6000
2262000	1	0.01	2262000	0.60	1	1:1	6000
2445000	1	0.01	2445000	0.65	1	1:1	6000
2454000	1	0.01	2454000	0.65	1	1:1	6000
2655000	1	0.01	2655000	0.71	1	1:1	6000
2724000	1	0.01	2724000	0.73	1	1:1	6000
2754000	1	0.01	2754000	0.73	1	1:1	6000
2766000	4	0.02	11064000	2.95	4	1:4	24000
3000 additional shares are allocated						1:4	3000
2892000	1	0.01	2892000	0.77	1	1:1	6000
2910000	10	0.06	29100000	7.75	10	1:1	60000
Total	**16164**	**100.00**	**375594000**	**100.00**	**271**		**900000**

4. Allocation to Eligible Employees (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to Eligible Employees, who have Bid at or above the Issue Price per Equity Share was finalised in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category has been subscribed to the extent of **2.80** times. The Total number of Equity Shares allotted in this category is **30000** Equity Shares to **7** successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of applications received	% Of Total	Total No. of shares applied in each category	% Of Total	No. of successful applicants	Ratio	Total no. of Shares Allotted
12000	7	100.00	21000	100.00	7	1:1	21000
3000 additional shares are allocated					3	3:7	9000
Total	**7**	**100.00**	**21000**	**100.00**			**30000**

5. Allocation to Eligible Shareholder Category (After Technical Rejections):

The Basis of Allotment to Shareholder Category, who have Bid at or above the Issue Price per Equity Share was finalised in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category has been subscribed to the extent of **6.61** times. The Total number of Equity Shares allotted in this category is **300000** Equity Shares to **100** successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of shares applied for (Category wise)	No. of applications received	% Of Total	Total No. of shares applied in each category	% Of Total	No. of successful applicants	Ratio	Total no. of Shares Allotted
3000	661	100.00	1983000	100.00	100	100:661	300000
Total	**661**	**100.00**	**1983000**	**100.00**			**300000**

6. Allocation to Market Maker (After Technical Rejection):

Allotment to Market Maker, who have Bid at or above the Issue Price of ₹ 38/- per Equity Share was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The Category has been subscribed to the extent of 1 time of Market Maker portion. The Total number of Equity Shares allotted in this category is 3,60,000 Equity Shares to 1 successful applicant.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on **August 02, 2024** has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. **National Stock Exchange of India Limited** and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice cum refund intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories. Further, the instructions to SCSBs have been dispatched / mailed for unblocking of funds and transfer to the public issue account on or before **August 05, 2024.** In case the same is not received within ten days, Investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allocated to successful allottees shall be uploaded on or before **August 05, 2024** for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from Designated Stock Exchange viz. **National Stock Exchange of India Limited** and trading of the Equity Shares is expected to commence on **August 06, 2024.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated **August 01, 2024** ("Prospectus") filed with the Registrar of Companies, Jaipur **("RoC").**

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Bidder Serial number of the ASBA Form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the acknowledgement slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Office No, S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Next to Ahura Centre, Andheri (East), Mumbai - 400 093 India

Tel No.: +91 022-6263 8200; **Fax No.:** +91 022-6263 8299; **Email:** ipo@bigshareonline.com

Website: www.bigshareonline.com; **Contact Person:** Mr. Jibhu John

SEBI Registration No.: INR000001385; **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com

For Rajputana Industries Limited
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Shivani Sheikh
Chairman & Managing Director

Place: Jaipur
Date: 03.08.2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF RAJPUTANA INDUSTRIES LIMITED.

Disclaimer: Rajputana Industries Limited has filed the Prospectus with Roc on **August 01, 2024** and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and on the websites of BRLM, Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in. The investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, refer to the Section titled **"Risk Factors"** on page **31** of Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended **("U.S. Securities Act"),** and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales occur. There will be no public offering in the United States.

ramaads

बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़ा

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,703 करोड़ रुपये रहा है। बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने बताया कि उसका मुनाफा खराब ऋणों से निपटने के लिए अलग रखी गई धनराशि में वृद्धि के कारण सीमित रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 1,551 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय जून तिमाही के लिए छह प्रतिशत बढ़कर 6,275 करोड़ रुपये रही है।

इसमें अग्रिमों में लगभग 16 प्रतिशत की उछाल और शुद्ध ब्याज मार्जिन के 0.04 प्रतिशत बढ़कर 3.07 प्रतिशत होने का भी योगदान है।बैंक की गैर ब्याज आय जून तिमाही में घटकर 1,302 करोड़ रुपये रह गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,462 करोड़ रुपये थी। बैंक की जमा वृद्धि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान 9.74 प्रतिशत रही है।

ऋण विस्तार के मोर्चे पर, खुदरा और कृषि दोनों ने तिमाही के दौरान 20 प्रतिशत से अधिक की अच्छी वृद्धि दिखाई, जबकि एमएसएमई खंड में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून तिमाही के अंत में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात सुधरकर 4.62 प्रतिशत हो गया। खराब परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बढ़कर 1,215 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 776 करोड़ रुपये था। यह आय वृद्धि को सीमित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक प्रतीत होता है। ऋणदाता के लिए कुल पूंजी पर्याप्तता 16.18 प्रतिशत रही, जबकि मुख्य बफर स्तर 13.62 प्रतिशत रहा।

अमारा राजा एनर्जी का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 26 प्रतिशत बढ़कर 249 करोड़ रुपये रहा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी (एआरईएंडएम) का चालू वित्त वर्ष (2024-25) की अप्रैल-जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 26 प्रतिशत बढ़कर 249.12 करोड़ रुपये रहा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 198.31 करोड़ रुपये रहा था। अमारा राजा एनर्जी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी परिचालन आय जून तिमाही में बढ़कर 3,263.05 करोड़ रुपये रही है, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,796.27 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद रेंज का निर्माण जारी रखेगी, नए क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी और अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करेगी। एआरईएंडएम ऊर्जा भंडारण समाधान, लिथियम-आयन सेल विनिर्माण, ईवी चार्जर, ऑटोमोटिव और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत है।

'भारत चावल और अन्य फसलों के मामले में आत्मनिर्भर, लेकिन तिलहन की फसलों के विविधीकरण में सुधार करना होगा।'

कृषि सम्मेलन में दुनिया भर के कृषि विशेषज्ञों ने शेयर किए अपने अनुभव

बिज़नेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएएनएस

दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र में 32वां एग्रीकल्चर सम्मेलन चल रहा है। 65 साल बाद भारत में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।

इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना और कृषि में नए बदलाव लाना है। सम्मेलन में कई देशों की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपना अनुभव शेयर किया। झेजियांग विश्वविद्यालय के पीएचडी के छात्र जेन लियू ने कहा कि मैं सम्मेलन में दुनिया भर के कई उत्कृष्ट शोधकर्ताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना चाहता हूं और प्रोफेसरों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं इंडिया गेट समेत भारत की शानदार इमारतों की वास्तुकला और सुंदरता को देखने समझने के लिए मौके पर जाना चाहता हूं।÷

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि डॉ. अंजनी कुमार कहते हैं, 'ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक मुद्दा है और वैज्ञानिक व विशेषज्ञ इसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में, किसानों को इसके प्रभावों से बचाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित हैं।'

घाना विश्वविद्यालय से आए डॉ. अल्फ्रेड असुमिंग बोआके ने कहा कि उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। दो बातें जो दिमाग में आती हैं, वे हैं जल उपयोग में सुधार करना और कुशल सिंचाई प्रणालियों को लागू करना।

एकेडमी ऑफ ग्लोबल फूड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के डीन शेंगगेन फैन ने कहा कि मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैंने भारत में जो बदलाव देखे हैं, उनमें खाद्य और कृषि उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि शामिल है, इससे कुपोषण में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, खेती की अवधारणाओं में सुधार हुआ है।

जीआईडीआर के पूर्व निदेशक एस.महेंद्र देव कहते हैं, कि भारत चावल और अन्य फसलों के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन तिलहन की हमारे पास कमी है, इसलिए हमें फसलों के विविधीकरण में सुधार करना होगा।' इस सम्मेलन की खासियत यह है कि आप दुनिया भर में कृषि के क्षेत्रों में हो रहे विभिन्न अनुसंधानों को जान सकते हैं।

आईआरआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अलीशेर मिर्जाबाएव कहते हैं,'हम कृषि में भारतीय अनुभवों के बारे में बहुत दिलचस्प प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से बहुत कुछ सीख रहा हूं, न केवल भारत की सफलताओं के बारे में बल्कि उन योजनाओं के बारे में भी, जो भारत में शोधकर्ताओं के पास भविष्य के लिए मौजूद हैं।' इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स' है। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ कृषि की तरफ ध्यान देना है। सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएई) 65 वर्षों के बाद भारत में हो रहा है। मैं भारत के 120 मिलियन किसानों, 30 मिलियन से अधिक महिला किसानों, 30 मिलियन मछुआरों और 80 मिलियन पशुपालकों की ओर से सभी गणमान्यों का स्वागत करता हूं। आप उस भूमि पर हैं, जहां 500 मिलियन से अधिक पशुधन हैं। मैं आपका कृषि और पशु-प्रेमी देश भारत में स्वागत करता हूं। भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन यहां की कृषि और खाद्यान्न को लेकर हमारी मान्यताएं और अनुभव हैं।

कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने मखाना महोत्सव का उद्घाटन किया

बज़नेस रेमेडीज/ पटना/आईएएनएस

बिहार की राजधानी पटना में आयोजित दो दिवसीय मखाना महोत्सव का प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों में मखाने की खेती को लेकर दिलचस्पी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में कहीं भी मखाने की बात होती है तो बिहार का नाम आता है। मखाना बिहार की पहचान बन गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस महोत्सव के आयोजन का मकसद है कि बिहार में होने वाली मखाने की प्रसिद्धि और बढ़े।बिहार की सरकार किसानों के उत्पादन को बढ़ाने और उसे बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। हमारे किसान समृद्ध हों, यही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया का 85 प्रतिशत मखाना बिहार में पैदा होता है। फिलहाल, प्रदेश के करीब 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है, जिसमे 25 हजार किसान लगे हुए हैं। बिहार सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए हमें आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके मखाने के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होगा।

मखाना महोत्सव का आयोजन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा, ताकि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। इस मौके पर बिहार के विभिन्न जिलों के मखाना उत्पादक अपने-अपने मखाना प्रोडक्ट्स के साथ पहुंचे। लोगों को मखाने के बने गुलाब जामुन, पेड़ा, लड्डू, बिस्कुट काफी पसंद आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मिथिला मखाने को जीआई टैग दिया गया है, वह मखाना उत्पादन के क्षेत्र में बिहार की विशिष्टता को दर्शाता है। साथ ही इस आयोजन के दौरान उत्पादन से संबंधित विकसित नई तकनीक का प्रदर्शन और मखाना क्षेत्र के विकास की दिशा में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए प्रगतिशील कदम को भी साझा किया जा रहा है। बता दें कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णियां, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज मखाना के प्रमुख उत्पादक जिले हैं।

'ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी, इन उपक्रमों से होगा 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश'

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास एवं संचालन के लिए संयुक्त उपक्रम, अक्षय एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा विद्युत प्रसारण परियोजनाओं के लिए संयुक्त उपक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदनाम परिवर्तन एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सूपर स्पेशियलिटी शिक्षकों की कमी दूर करने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम : उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह संयुक्त उद्यम राजस्थान में वर्तमान में चल रही एवं भविष्य की मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास, परिचालन एवं क्रियान्वयन के लिए होगा।

अक्षय, तापीय ऊर्जा एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए ज्वाइंट वेंचर : संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार और विभिन्न केन्द्रीय पीएसयू के बीच हुए एमओयू की अनुपालना में मंत्रिमंडल की बैठक में आज भारत सरकार की विभिन्न पीएसयू के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनियों के गठन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और केन्द्रीय पीएसयू कंपनियों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत रहेगी। इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर हॉलिंडग के लिए वर्तमान परिसंपत्तियों से अंश पूंजी व्यवस्था की जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उपक्रम : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड और आरवीयूएनएल के बीच दो अलग अलग जेवी की स्थापना की जाएगी। इसमें एक तापीय परियोजना एवं दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। इन जेवी से बिजली की बेस लोड और पीक लोड डिमांड पूरी होगी। साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में कमी आएगी। पहली परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध तापीय परियोजना झालावाड़ परिसर में 800 मेगावाट की इकाई या किसी अन्य पीटहैड ग्रीनफील्ड कोयला परियोजना की स्थापना की जाएगी। दूसरी जेवी के तहत दो हजार से ढाई हजार मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना, पंप स्टोरेज परियोजना और पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं से 17 हजार 200 से 24 हजार 400 करोड़ रूपये का प्रदेश में निवेश होगा।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य संयुक्त उपक्रम : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एवं आरवीयूएनएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर बनाई जाएगी। यह उपक्रम 25 हजार मेगावाट की सोलर/ विंड/ हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश में एक लाख करोड़ रूपये का निवेश होगा।

'भारत में खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 3 प्रतिशत बढ़कर 904.60 लाख हेक्टेयर हुआ'

बिज़नेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएएनएस

भारत में इस वर्ष खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 3 प्रतिशत बढ़कर 904.60 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 879.22 लाख हेक्टेयर था। कृषि मंत्रालय की ओर से एकीकृत किए गए डेटा से यह जानकारी मिली है।

धान, दलहन, तिलहन, बाजरा, और गन्ना जैसी मुख्य फसलों की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। इसकी वजह देश में सामान्य से अच्छा मानसून होना है। कृषि क्षेत्र में आगे और बढ़त देखने को मिल सकती है। इसकी वजह आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने और लचीलापन लाने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करना है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए किए गए ऐलानों में तिलहन में आत्मनिर्भरता और सब्जी उगाने के लिए बड़े स्तर का क्लस्टर आदि शामिल है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की रणनीति सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, और सूरजमुखी जैसे तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री की ओर से आगे कहा गया है कि बड़े स्तर पर सब्जी उत्पादन के क्लस्टर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे, जहां खपत काफी ज्यादा है। सरकार उत्पादों के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। सरकार की ओर से सभी बड़ी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल की लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन मिल सके।

टाटा का असम संयंत्र करेगा प्रतिदिन 4.8 करोड़ चिप्स का उत्पादन, 28,000 नौकरियों का सृजन होगा : अश्विनी वैष्णव

बिज़नेस रेमेडीज/ नई दिल्ली/आईएएनएस

केंद्रीय रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि असम में टाटा समूह का सेमीकंडक्टर संयंत्र एक दिन में 4.83 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र चालू होने पर 15,000 प्रत्यक्ष और 13,000 तक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सेमीकंडक्टर यूनिट स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के विकास की एक साइट होगी, जिसमें वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप और आई-एसआईपी (इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज) तकनीक शामिल हैं।

मंत्री के अनुसार, यह तकनीक ऑटोमोबाइल (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन), संचार, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे प्रमुख एप्लीकेशन्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश भर के

113 शैक्षणिक संस्थानों में से नौ पूर्वोत्तर में स्थित है, जहां बीटेक, एमटेक और पीएचडी स्तर पर लगभग 85,000 इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स को सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से कहा, ÷प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा एक्ट ईस्ट नीति पर जोर दिया है और इस फैसिलिटी के निर्माण की शुरुआत के साथ, असम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया जा रहा है। सरकार के अनुसार, असम संयंत्र 27,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया जाएगा और इससे 15,000 प्रत्यक्ष और 11,000-13,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक आधारभूत उद्योग के रूप में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे उद्योगों में कई स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

लीड का 2024 मास्टरक्लास भारत के स्कूलों में लाएगा विविध नृत्य शैलियां

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

भारत की अग्रणी स्कूल एडटेक कंपनी लीड ग्रुप ने अपनी नवीनतम मास्टरक्लास सीरीज़ की घोषणा की है, जो देश भर के स्कूली छात्रों तक पारंपरिक और समकालीन दोनों प्रकार के नृत्य पेश करेगी। एसआईएफएफ यंग आर्टिस्ट के सहयोग से लॉन्च किया गया लीड ग्रुप का 2024 मास्टरक्लास छात्रों को तीन प्रतिष्ठित नृत्य रूपों से परिचित कराएगा जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं- ऊर्जावान भांगड़ा, सुंदर कथक और गतिशील फ़्रीस्टाइल। लीड का मास्टरक्लास अद्वितीय अनुभव, प्रदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करता है जो अन्यथा भारत के छोटे शहरों में छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

लीड की मास्टरक्लासेस का संचालन प्रसिद्ध नृत्य उस्तादों द्वारा किया जाएगा। 'नृत्य अलंकार' से सम्मानित अनुष्का चांडक, कथक की शाश्वत सुंदरता को मूर्त रूप प्रदान करेंगी; भारतीय हिपहॉप चैंपियन दीपक देवरानी, ??भांगड़ा संगीत में आधुनिक ऊर्जा का संचार करेंगे और इअंडियन साल्सा प्रिंसेस स्नेहा कपूर, पूर्वी और पश्चिमी नृत्य परंपराओं को जोड़ेंगी।

इन मास्टरक्लास के माध्यम से, लीड संचालित स्कूलों के छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलेंगे। पाठ्यक्रम में नृत्य को एकीकृत करके, छात्र संचार, सहयोग और रचनात्मकता जैसे महत्वपूर्ण 21वीं सदी के कौशल विकसित करेंगे। यह दृष्टिकोण न केवल आत्म-अभिव्यक्ति के नए रास्ते को बढ़ावा देता है, बल्कि छात्रों को एक अच्छी तरह से गोल, आकर्षक और समृद्ध शैक्षिक अनुभव में अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने में भी मदद करता है।

लीड ग्रुप के साथ साझेदारी पर एसआईएफएफ की संस्थापक कविता अय्यर ने कहा कि एसआईएफएफ में, हम शिक्षा और कला की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं। आगामी डांस मास्टरक्लास श्रृंखला के लिए लीड ग्रुप के साथ हमारी साझेदारी हमें एक दिन हर व्यक्ति को अपने चुने हुए कला रूप में एक उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त होगी÷ के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। फ़्रीस्टाइल, भांगड़ा और कथक जैसे विविध नृत्य रूपों पर ध्यान केंद्रित करने वाले इन मास्टरक्लास के माध्यम से, हमारा उद्देश्य छात्रों के बीच रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को प्रेरित करना है। हम इन सत्रों का छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए उत्साहित हैं।

लीड ग्रुप के सह-संस्थापक और सीईओ सुमीत मेहता ने कहा कि परफार्मिंग आर्ट बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं, जो आत्म-अभिव्यक्ति के लिए एक रचनात्मक आउटलेट प्रदान करती हैं। नृत्य रूपों पर लीड की मास्टरक्लास श्रृंखला का उद्देश्य इस अंतर को भरना और छात्रों को खुद को अभिव्यक्त करने में अधिक आत्मविश्वास बनाने में मदद करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) भी बच्चों में वास्तविक जीवन कौशल और एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया में कला को एकीकृत करने के महत्व पर जोर देती है।

अमित शाह ने चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया

बिज़नेस रेमेडीज/ चंडीगढ़/आईएएनएस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां मनीमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चंडीगढ़ के लिए चौबीसों घंटे जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इससे एक लाख से ज्यादा निवासियों को फायदा होगा। परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। जब यह साफ नहीं होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से फिल्टर-क्लीन पानी की चौबीसों घंटे सातों दिन आपूर्ति की जाएगी। यह समय की कसौटी पर खरा उतरेगा।

अमित शाह शाम पांच बजे शहर से रवाना होने से पहले सचिवालय में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री सीधे मनीमाजरा पहुंचे और 75 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना का उद्घाटन किया। इससे मनीमाजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिलेगा, जिनमें मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी और शास्त्री नगर में रहने वाले लोग शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे सातों दिन उच्च दबाव आपूर्ति कर जनता द्वारा पानी के स्टोरेज को न्यूनतम करके पानी की बर्बादी को रोकना है। परियोजना की अन्य विशेषताओं में रिसाव में कमी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि, स्मार्ट मीटरिंग, अंडरग्राउंड वाटर पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी शामिल हैं। इस परियोजना के लिए कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है। दो भूमिगत (अंडरग्राउंड) जलाशय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 20 लाख गैलन प्रतिदिन है। सिटी ब्यूटीफुल का लगभग 270 किलोमीटर लंबा जल आपूर्ति नेटवर्क, जो उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसे भी बाद में बदल दिया जाएगा। इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसके लिए शहर को 55 जिला मीटरिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उम्मीद है कि 2028 तक पूरे शहर को कवर कर लिया जाएगा।

BR

सम्पादकीय

देश में फैलता कोचिंग इंडस्ट्री का जाल, पर नियमों की होती अनदेखी

देश में आज कोचिंग इंडस्ट्री की बाढ़-सी आई हुई है। करीब-करीब सभी राज्यों में यही हाल है। अधिकांश कोचिंग संस्थान बिना नियम कायदों के चल रही हैं। दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोचिंग इंडस्ट्री सवालों के घेरे में आ गई है। छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने, छात्रों पर ज्यादा तनाव थोपने जैसी समस्याओं को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए 16 जनवरी, 2024 को गाइडलाइंस तो जारी की थी, लेकिन यह काफी नहीं। कोचिंग सेंटर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देते, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से छात्रों की जान पर खतरा है। इसे हर हाल में रोकना होगा। केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर छात्रों के हित वाली पॉलिसी पर काम करना होगा। देश में यह इंडस्ट्री इतनी तेजी से फैली है इसका अंदाजा जीएसटी कलेक्शन से भी लगा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार-पांच साल में कोचिंग इंस्टिट्यूशन से मिलने वाले जीएसटी कलेक्शन में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में जहां कोचिंग संस्थानों से 2240.73 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन मिला, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 5517.45 करोड़ हो गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी यह माना गया है कि छात्रों के साथ-साथ उनके पैरेंट्स बेहतर रिजल्ट के लिए कोचिंग को चुन रहे हैं। विषय को समझाने की जगह रटने पर फोकस कराया जा रहा है। समाधान के लिए नई शिक्षा नीति में रेगुलर फोरमेटिव असेसमेंट की सिफारिश की गई है। सिर्फ रटने और परीक्षा-केंद्रित तैयारी पर जोर देने वाली कोचिंग संस्कृति के प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। पैरेंट्स व छात्रों पर कोचिंग का बुखार इस कदर हावी है कि वे डमी स्कूलों में चले जाते हैं। डमी स्कूलों में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और क्लास कोचिंग में लेते हैं। जबकि स्कूल जाने से बच्चा ज्यादा सीखता है, उस पर तनाव कम हावी होता है। जहां वर्ष, 2024 में सरकार ने जेईई मेन के साथ-साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के सिलेबस में भी कटौती की थी। बड़े एंट्रेंस टेस्ट बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में पढ़े गए कोर सब्जेक्ट के आधार पर कराए गए हैं। यानी बोर्ड क्लासेज में अच्छी तरह से पढ़ने वाले छात्र इन बड़े एंट्रेंस टेस्ट को बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हैं। जेईई एक वर्ष में दो बार होती है ताकि छात्र बेस्ट स्कोर चुन सके। सीयूईटी, जेईई और नीट देश की 13 भारतीय भाषाओं में कराई जाती है। अब सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए हाई लेवल कमिटी भी बनाई है, जो तीन स्तर की रणनीति पर काम कर रही है।

पुनीत जैन

BR

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विशेष लेख व्यक्तिगत सोच के आधार पर है।

-संपादक

ई-मित्र केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण की आवश्यकताः एक जरूरी कदम

ई-मित्र केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, इन केंद्रों के संचालन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक हैं।

सुनील दत्त गोयल

महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जयपुर, राजस्थान

ई-मित्र केंद्रों की मौजूदा स्थिति

वर्तमान में, ई-मित्र केंद्रों का संचालन करने वाले अक्सर ठेके पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो स्थानीय युवाओं को इस काम के लिए नियुक्त करते हैं। इन युवाओं को न केवल रोजगार मिलता है, बल्कि वे इन केंद्रों पर अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। यह देखा गया है कि कई मामलों में, ई-मित्र केंद्रों के संचालक सरकारी निर्धारित फीस न लेकर अपनी मर्जी से फीस वसूलते हैं। इसके अलावा, जो लोग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आते हैं, उनके पासवर्ड, ओटीपी जैसी संवेदनशील जानकारियों का दुरुपयोग भी होता है।

ग्रामीण और कम जानकार नागरिक, जिनके पास खुद के घरों में कंप्यूटर नहीं होते या जो तकनीकी ज्ञान से वंचित होते हैं, अक्सर ई-मित्र केंद्रों पर निर्भर होते हैं। ये नागरिक अपनी मासूमियत के चलते उन कर्मियों के शिकार बनते हैं, जो भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होते हैं। यह भी देखा गया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, और अन्य दस्तावेजों की फर्जीवाड़ा करके जारी किए जाते हैं।

सुधार की आवश्यकता

ई-मित्र केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण की आवश्यकताः एक जरूरी कदम

सरकार को इन केंद्रों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ई-मित्र केंद्रों का संचालन करने वाले संचालक पूरी तरह से जवाबदेही के दायरे में हों। केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों की पूरी केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, और किसी भी अनियमितता के पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा, जो लोग फर्जीवाड़े में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें आजीवन इस तरह की सेवाओं से संबंधित किसी भी रोजगार से वंचित किया जाना चाहिए। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार को कम करेगा, बल्कि जनता की सेवा में सुधार भी लाएगा।

तकनीकी निरीक्षण और प्रशिक्षण

ई-मित्र केंद्रों की तकनीकी संरचना की नियमित जांच भी आवश्यक है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ई-मित्र केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों को उचित तकनीकी प्रशिक्षण मिले, जिससे वे नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रख सकें। इसके अलावा, नागरिकों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि वे अपने संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।

डिजिटल भुगतान और रिकॉर्ड की पारदर्शिता

सरकार को ई-मित्र केंद्रों में डिजिटल भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे नकद लेनदेन की संभावनाएं कम हो सकें और लेनदेन की पारदर्शिता बढ़े।

इससे नागरिकों के लिए सेवाओं की लागत का ट्रैक रखना आसान हो जाएगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी घटेगी। साथ ही, सभी लेनदेन और सेवाओं का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद या अनियमितता की स्थिति में जांच में आसानी हो।

समुदाय की भागीदारी और निगरानी

समुदाय की भागीदारी और निगरानी से ई-मित्र केंद्रों के कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ सकती है। सरकार स्थानीय समुदायों, निकायों और संगठनों को इस प्रक्रिया में शामिल कर सकती है, जिससे केंद्रों के संचालन की निगरानी अधिक प्रभावी हो सके। इसके लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकें और उन्हें समय पर निवारण मिल सके।

निष्कर्ष

ई-मित्र केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरकार को इन केंद्रों पर सख्त नियंत्रण रखते हुए, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। इससे न केवल जनता की सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों का विश्वास भी बहाल होगा। तकनीकी निरीक्षण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, डिजिटल भुगतान की प्रवृत्ति, और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से, ई-मित्र केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

महिन्द्रा युनिवर्सिटी ने तीसरा दीक्षांत समारोह में 751 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की

बिज़नेस रेमेडीज/हैदराबाद

महिन्द्रा युनिवर्सिटी ने अपने परिसर में अपने तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जिसमें 751 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। समारोह के दौरान, असाधारण अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान उपलब्धियां प्रदर्शित करने एवं समुदाय में योगदान करने वाले विद्यार्थियों को मेडल से सम्मानित किया गया। इस वर्ष का दीक्षांत समारोह, एक्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए पहला दीक्षांत समारोह है।

आयोजन की अध्यक्षता महिन्द्रा युनिवर्सिटी के कुलाधिपति आनंद महिन्द्रा ने की और तेलंगाना सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री दामोदर राजानरसिम्हा मुख्य अतिथि थे, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइस की प्रवर्तक निदेशक और अपोलो हेल्थ एंड अपोलो फार्मासीज़ की कार्यकारी चेयरपर्सन शोभना कामिनेनि विशिष्ट अतिथि थीं। महिन्द्रा युनिवर्सिटी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य सीपी गुरनानी, महिन्द्रा युनिवर्सिटी के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य मोहित जोशी और प्रबंधन बोर्ड की सदस्य अनुजा महिन्द्रा भी उपस्थित थीं। राजानरसिम्हा और कामिनेनि ने महिन्द्रा युनिवर्सिटी में स्टूडेंट रेसिडेंट हॉल का उद्घाटन किया।

महिन्द्रा युनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए तेलंगाना सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री

दामोदर राजानरसिम्हा ने कहा कि 21वीं शताब्दी परिवर्तन से संचालित है और टेक्नोलॉजी इस दुनिया को एक सूत्र में बांध रही है। इस दुनिया में हासिल करने के लिए असीमित ज्ञान है और समझदारी के साथ निर्णय में इससे मदद मिलती है। इस तेजी से बदलती दुनिया में संस्कृति, शिक्षा और मूल्य व्यक्ति को दूसरों से अलग करते हैं। महिन्द्रा युनिवर्सिटी ऐसे गतिशील विद्यार्थियों का पोषण कर रही है जो जोखिल उठाने के इच्छुक हैं और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइस की प्रवर्तक निदेशक और अपोलो हेल्थ एंड अपोलो फार्मेसीज की कार्यकारी चेयरपर्सन शोभना कामिनेनि ने कहा कि युवाओं को आज की डिजिटल दुनिया में गहन चिंतन पर केंद्रित होना चाहिए। सही नेतृत्व और बेहतर अनुसंधान में महिन्द्रा युनिवर्सिटी का निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर इसकी शानदार प्रतिष्ठा में एक प्रमुख कारक है। मेरा मानना है कि इस उद्योग में गहरी जड़े जमाए शैक्षणिक संस्थान तीन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिनमें प्रासंगिक नौकरियां उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना एवं लंबे समय तक पेशेवर कौशल के लिए कौशल विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं रीयल टाइन लर्निंग के लिए पहुंच सुगम बनाना शामिल है।

महिन्द्रा युनिवर्सिटी के कुलाधिपति आनंद महिन्द्रा ने उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के लिए एक सादृश्य के रूप में मधुमक्खी के छत्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि मधुमक्खी के छत्ते गतिविधियों का केंद्र होते हैं, लेकिन साथ ही इनमें वजह और मजबूती के बीच एक बढ़िया संतुलन भी होता है। इसी प्रकार से, उच्च गुणवत्ता के विश्वविद्यालय विभिन्न उद्देश्यों और परिणामों के बीच एक संतुलन रखते हैं।

महिन्द्रा ने कहा कि महिन्द्रा युनिवर्सिटी को इसके शुरुआती वर्षों में इस तरह की अविरल चाल से बढ़ते देख मुझे खुशी हो रही है। इस युनिवर्सिटी का लक्ष्य ना केवल तकनीकी क्षेत्रों में सीखने का एक केंद्र बनना है, बल्कि यह व्यापक विचारक तैयार करने में भी मदद करता है जो टेक्नोलॉजी और मानविकी के बीच संबंधों को समझते हैं और एप्लीकेशन एवं थ्योरी दोनों के संदर्भ में बात करते हैं।

अदाणी पोर्ट्स ने पहली तिमाही में दर्ज किया 3,107 करोड़ रुपये का मुनाफा, आय 21 प्रतिशत बढ़ी

बिज़नेस रेमेडीज/ अहमदाबाद/आईएएनएस

अदाणी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत बढ़कर 3,107 करोड़ रुपये हो गया है। अप्रैल से जून तिमाही में अदाणी पोर्ट्स का ईबीआईटीडीए बढ़कर 4,848 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में अदाणी पोर्ट्स की आय 21 प्रतिशत बढ़कर 7,560 करोड़ रुपये हो गई है। अप्रैल-जून की अवधि में कंपनी का वॉल्यूम 8 प्रतिशत बढ़कर 109 एमटी हो गया है।अदाणी पोर्ट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा कि वित्त वर्ष 25 की शुरुआत काफी मजबूत हुई है। वित्तीय मोर्चे पर हमने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली तिमाही में कार्गो वॉल्यूम 13 प्रतिशत बढ़कर 114.7 एमएमटी हो गया है। गुप्ता ने आगे कहा कि वृद्धि के मोर्चे पर हमने दो नए पोर्ट के कन्सेशन एग्रीमेंट और एक पोर्ट को ऑपरेशन और मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे चार पोर्ट को वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स 2023 में जगह दी गई है। कार्गो वॉल्यूम के तहत कंटेनर वॉल्यूम में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत और लिक्विड एंड गैस वॉल्यूम में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत की बढ़त हुई है।

जीएसटी कलेक्शन में आया 10 प्रतिशत का उछाल, सरकारी खजाने में आए 1.82 लाख करोड़ रुपए

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

जुलाई 2024 में 1,82,075 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन (रहा है जो जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ रुपए रहा था। बीते साल समान महीने के मुकाबले जुलाई 2024 में 10.2 फीसदी ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने में सफलता मिली है। जून 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूली में सफलता मिली थी। एक जुलाई, 2024 को वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया गया था लेकिन जीएसटी काउंसिल के पोर्टल पर इस बार ये डेटा अपलोड किया गया है।

जून 2024 का जीएसटी कलेक्शन : जून 2024 में जीएसटी वसूली 1.74 लाख करोड़ रुपए रही थी। एक जुलाई 2024 को वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया गया था, लेकिन जीएसटी काउंसिल के पोर्टल पर यह डेटा अपलोड किया गया है।

वृद्धि का कारणः जीएसटी कलेक्शन में यह वृद्धि विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे व्यापार और उद्योगों में बढ़ोतरी, टैक्स अनुपालन, व सरकार की ओर से की गई निगरानी।

महत्व : जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि सरकार की राजस्व स्थिति को मजबूत करती है और उसे विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है।

परिणामः यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार और स्थायित्व को दर्शाती है, साथ ही व्यापार और उद्योग में विश्वास की वापसी को भी इंगित करती है।

IIM रायपुरः पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम का पहली बैच का समारोह सम्पन्न

बिज़नेस रेमेडीज/रायपुर

भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर (IIM रायपुर), जो एक शीर्ष रैंकिंग वाला बिजनेस स्कूल है, ने डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल (CDHP) की पहली पोस्ट-ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्नातक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (भारत) थे। इस कोर्स को IIM रायपुर और डिजिटल हेल्थ साइंसेज अकादमी (ADHS) ने संयुक्त रूप से पेश किया था। IIM रायपुर के निदेशक प्रो. राम कुमार ककानी ने सभी स्नातक छात्रों का स्वागत किया। ADHS के संस्थापक डॉ. राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया।

ADHS के साथ साझेदारी में, IIM रायपुर ने स्वास्थ्य नवाचार नीति और डिजिटल हेल्थ के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण, नवाचार और नीति विकास के माध्यम से भारत को डिजिटल हेल्थ में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है। कुल 41 छात्रों ने 20 जुलाई 2024 को स्नातक किया, जिनमें से 12 महिलाएं और 29 पुरुष हैं। डॉ. आशीष कुमार गुप्ता को सर्वोच्च अंक के लिए निदेशक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। ये छात्र स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिनमें वरिष्ठ डॉक्टर, सर्जन, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, फार्मास्युटिकल, मेड-टेक और डिजिटल हेल्थ क्षेत्रों के वरिष्ठ पेशेवर, सरकारी अधिकारी और वरिष्ठ अकादमिक शामिल हैं, जिनके पास औसतन 20 वर्षों का कार्य अनुभव है।

यह कार्यक्रम एक वैश्विक

दृष्टिकोण को शामिल करता है, जिसमें डिजिटल हेल्थ के विश्व-प्रसिद्ध नेताओं और प्रैक्टिशनर्स के साथ सहयोग किया जाता है और दुनिया भर से डिजिटल हेल्थ पर व्यापक दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है। दुनिया के शीर्ष नेताओं के साथ लाइव इंटरैक्शन सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी न केवल सही ज्ञान से लैस हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर नेतृत्व करने के लिए प्रेरित भी हैं। ऑनलाइन डिलीवरी प्रारूप पेशेवरों को विश्व स्तर पर भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे एक विविध सीखने का वातावरण बनता है। इस कोर्स के चेयर विश्व के प्रमुख डिजिटल हेल्थ विशेषज्ञ हैं। डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब समय है कि डिजिटल तकनीकों और चिकित्सा विज्ञान का संगम हर समाज के वर्ग को लाभान्वित करे। आइए हम राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हों।

IIM रायपुर के निदेशक डॉ. राम कुमार ककानी ने कहा, कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों को डिजिटल हेल्थ में आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। हमारा दृष्टिकोण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं को तैयार करना है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। हम डिजिटल हेल्थ में दुनिया का सबसे अच्छा कार्यक्रम बने रहने और डिजिटल हेल्थ में वैश्विक नेताओं को बनाने की इच्छा रखते हैं। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित नेता डिजिटल उपकरणों के साथ परामर्श कंपनियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों, मेड-टेक कंपनियों और अस्पतालों के साथ काम करते हुए स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देंगे। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अभिनव उत्पाद, परियोजनाएं और कार्यक्रम विकसित करें जो स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाएं।

ADHS के संस्थापक डॉ. राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने कहा, कि भारत ने डिजिटल हेल्थ लीडर्स की पहली बैच तैयार की है, जिनके पास स्वास्थ्य सेवा के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने की क्षमता है। यह डिजिटल हेल्थ साइंसेज अकादमी ने IIM रायपुर के सहयोग से एक अद्वितीय कोर्स के माध्यम से वैश्विक रूप से ऑनलाइन पेश किया - पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिजिटल हेल्थ। यह कार्यक्रम पहले बैच के सर्टिफाइड डिजिटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को तैयार करता है।

निफ्टी में 25008 अंक के ऊपर तेजी देखी जा सकती है

निखिल भट्ट
रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत

दिनांक 05.07.2024 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में....

दिनांक 02.08.2024 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 24700 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 25188 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 24979 - 24909 - 24880 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 25202 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति....!!!

दिनांक 02.08.2024 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 51420 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित बैंक निफ्टी फ्यूचर 52008 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 51676 - 51606 - 51474 अंक को छू सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 52188 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति....!!!

अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

रिलायन्स इंडस्ट्रीज (3036) :- रिलायन्स ग्रुप की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 2970 रुपये के आसपास है। 2929 रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 3063 से 3070 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!! 3077 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!

ऐसीसी लिमिटेड (2502) :- तकनीकी चार्ट के अनुसार 2474 रुपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउट..!! 2460 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 2534 रुपये से 2560 रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना है...!!

ओबेरॉय रियलिटी (1850) :- रेसीडेनसियल एंड कोमसियल प्रोजेक्ट सेक्टर के शेयर में 1868 रुपये से 1880 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा,1808 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

इंडसइंड बेंक (1426):- प्राइवेट बेंक सेक्टर के शेयर में 1454 रुपये से 1460 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा, 1390 रुपये के अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें!!

एक्सिस बेंक (1175) :- 10 रुपये का फेसवैल्यूका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यह स्टॉक करीब 1155 स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकने प्राइवेट बेंक सेक्टर के इस स्टॉक में लगभग 1194 रुपये से 1203 रुपये तक लक्ष्य की संभावना है!!!

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (2836) :- तकनीकी चार्ट के पेसेंजर कार एंड यूटिलिटी विहिक्ल्स सेक्टर के इस शेयर पर बिकवाली होने की संभावना के साथ 2808 रुपये से 2790 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है । प्रतिक्रियात्मक के लिए 2909 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!

टाटा कम्युनिकेसन (1974) :- इस शेयर को 2008 / 2024 रुपये के आसपास ओवरबोट स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1960 रुपये से 1933 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 2030 रुपये के स्तर पर एक तेजी का माहोल..!!

ल्यूपिन लिमिटेड (1968) :- फार्मा सेक्टर का यह स्टॉक 2008 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1944 रुपये से 1930 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!

कोटक महिन्द्रा बेंक (1801) :- प्राइवेट बेंक सेक्टर के इस शेयर को करीब 1838 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1787 रुपये से 1770 रुपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1844 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का पालन करें...!!

एचडीफसी बेंक (1657) :- इस शेयर को करीब 1680 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 1640 रुपये से लेकर 1626 रुपये तक रहने की संभावना है। 1700 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!!

लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं।

विशेष नोट:- डिस्क्लेमर / नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!

नोट: शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए।

रिजर्व बैंक के ब्याज दर पर निर्णय, वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ब्याज दर पर निर्णय, वृहद आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक बाजारों के रुख से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय जताई है। विश्लेषकों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

सेवा क्षेत्र के एचएसबीसी पीएमआई (खरीद प्रबंधक सूचकांक) आंकड़ों की घोषणा सोमवार को होगी। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लि. के शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, ''इस सप्ताह सभी की निगाह वैश्विक बाजारों पर रहेगी। लंबे समय की स्थिरता के बाद अब बाजार में कमजोरी का कुछ संकेत दिखने लगा है। इससे भारतीय बाजार की मजबूती की परख होगी, जो तरलता की बेहतर स्थिति की वजह से अभी तक जुझारू बना हुआ है।'' मीणा ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर आठ अगस्त को आने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही के नतीजों के आखिरी दौर से बाजार में कुछ शेयर विशेष गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा संस्थागत प्रवाह भी बाजार की दिशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह के दौरान भारती एयरटेल, बीईएमएल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, भारतीय जीवन बीमा निगम और एमआरएफ जैसी बड़ी कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''आगे चलकर ऊंचे मूल्यांकन की वजह से बाजार में कुछ कमजोरी आ सकती है। इस सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक से ब्याज दरों के परिदृश्य पर कुछ संकेत मिलेगा।

फिलहाल केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर यथास्थिति बरकरार रख सकता है।'' पिछले सप्ताह बिकवाली दबाव के बीच बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शु वार को 885.60 अंक या 1.08 प्रतिशत गिरकर 80,981.95 अंक पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 293.20 अंक या 1.17 प्रतिशत फिसलकर 24,717.70 अंक रहा था। विश्लेषकों ने कहा कि बाजार भागीदारों की निगाह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा डॉलर के मुकाबले रुपये के रुख पर भी रहेगी।

इंफीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम की घोषणा की

बिजनेस रेमेडीज। भारत की पहली सूचीबद्ध एआई-पावर्ड टेक और फिनटेक कंपनी, इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड ('इन्फीबीम' या 'द कंपनी' या 'आईएएल'), (बीएसई: 539807; एनएसई: इंफीबीम), ने 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषणा की है।

समेकित वित्तीय प्रदर्शन समीक्षा: इंफीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में टैक्स के बाद 504 मिलियन रुपये के लाभ (पीएटी) के साथ 7,528 मिलियन रुपये का मजबूत समेकित सकल राजस्व दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के शुद्ध राजस्व में 20% की वृद्धि देखी गई, इसके बावजूद कि तिमाही के दौरान त्र्न्नरू से संबंधित प्लेटफ़ॉर्म पर राजस्व दर्ज नहीं किया गया, मुख्य रूप से भुगतान लेने की दर में वृद्धि के कारण तिमाही में 11.2 बीपीएस (पिछले वर्ष की समान तिमाही 8.4 बीपीएस से) तक बढ़ गया और शुद्ध मुनाफा में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 59 की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। एबिट्डा ने भी साल-दर-साल 25% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की और 698 मिलियन रुपये तक पहुंच गया।

ग्रोथ अट्रिब्यूट्स: बढ़ा हुआ भुगतान लेनदेन (टीपीवी) वॉल्यूम: पहली तिमाही के दौरान टीपीवी सालाना आधार पर 67% बढ़कर 1,977 बिलियन रुपये तक पहुंच गया। बढ़ी हुई टीपीवी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग और व्यापारियों के बीच डिजिटल पीओएस उत्पाद-सीसीएवेन्यू टैपपे के बढ़ते उपयोग के कारण कंपनी के व्यापारी आधार में वृद्धि के कारण है। हजारों थर्ड पार्टी व्यापारी सिस्टम में सीसी एवेन्यू के गहन एकीकरण ने निरंतर विकास और सफलता को बढ़ावा दिया।

बढ़ी हुई दर: पहली तिमाही में, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 8.4 बीपीएस से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 11.2 बीपीएस तक वृद्धि देखी। टेक रेट में यह वृद्धि इंफीबीम की टीमों के अनुशासन, निष्पादन, अनुकूलन और डिजिटल भुगतान की पुनर्कल्पना का परिणाम है।

मर्चेंट आधार में वृद्धि: व्यापारी आधार के निरंतर विस्तार ने कंपनी की उपलब्धियों को काफी हद तक बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 23-24 के अंत तक प्रभावशाली कुल 10 मिलियन से ज्यादा व्यापारी खाते होंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, कंपनी के कुल व्यापारी आधार में प्रतिदिन औसतन 2,550 से ज्यादा व्यापारी खातों के साथ पंजीकरण करने वाले व्यापारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि: कंपनी ने अपने भुगतान व्यवसाय के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय प्ले को और मजबूत किया, क्योंकि इसने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को फिर से व्यवस्थित किया और किंगडम ऑफ सऊदी अरब (KSA) से विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) बाजार में मोबाइल-आधारित क्त कोड भुगतान समाधान लॉन्च किया।

कोल इंडिया का उत्पादन चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में 6.6 प्रतिशत बढ़कर 24.43 करोड़ टन हुआ

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में 6.6 प्रतिशत बढ़कर 24.43 करोड़ टन हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने बीएसई को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में कंपनी का उत्पादन 22.91 करोड़ टन रहा था। कंपनी का उत्पादन जुलाई में 2.5 प्रतिशत बढ़कर 5.5 करोड़ टन हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में यह 5.37 करोड़ टन था। अप्रैल-जुलाई अवधि में कंपनी की आपूर्ति बढ़कर 25.72 करोड़ टन हो गई। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 24.63 करोड़ टन थी। कंपनी की आपूर्ति जुलाई में 5.96 करोड़ टन रही जबकि पिछले वर्ष इसी माह यह 5.95 करोड़ टन थी। कोल इंडिया की घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

आईटीसी का जून तिमाही में शुद्ध लाभ मामूली गिरावट के साथ 5,177 करोड़ रुपये रहा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत आईटीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में मामूली घटकर 5,176.99 करोड़ रुपये रहा है। आईटीसी लिमिटेड ने कहा कि उसके मुनाफे पर व्यापक आर्थिक चुनौतियों का असर पड़ा है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,189.61 करोड़ रुपये रहा था। आईटीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी परिचालन आय जून तिमाही में 7.45 प्रतिशत बढ़कर 20,029.60 करोड़ रुपये रही है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 18,639.48 करोड़ रुपये थी। आईटीसी का कुल खर्च जून तिमाही में 11.02 प्रतिशत बढ़कर 13,791.01 करोड़ रुपये रहा है।आईटीसी की कुल आमदनी (अन्य आय मिलाकर) बीते वित्त वर्ष की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में 7.03 प्रतिशत बढ़कर 20,724.48 करोड़ रुपये थी।

ब्रिटानिया का जून तिमाही का मुनाफा 11 प्रतिशत बढ़कर 505 करोड़ रुपये पर

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ 10.85 प्रतिशत बढ़कर 504.88 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने कहा कि यह मुनाफा मुख्यत: मात्रा बढ़ने और बेहतर परिचालन मार्जिन के चलते हुआ। कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही में 455.45 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि जून तिमाही में उत्पाद बिक्री से आय 4.03 प्रतिशत बढ़कर 4,129.92 करोड़ रुपये हो गई है।

एमओएस यूटिलिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने सौर व्यवसाय में प्रवेश कि दी मंजूरी

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। एमओएस यूटिलिटी लिमिटेड (NSE: MOS) एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है, जो व्यवसायों और व्यक्ति यों को विभिन्न प्रकार की फिनटेक और यूटिलिटी भुगतान समाधान सेवाएं देती है। कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि बोर्ड ने कंपनी के संस्थापन पत्र के उद्देश्य वाक्य में बदलाव किया है। कंपनी ने अपने मुख्य उद्देश्यों में कुछ नई व्यावसायिक गतिविधियों को जोड़ा है, जिसमें भारत या विदेश में सभी प्रकार के - सौर पीवी मॉड्यूल, सेल, बैटरी और ऊर्जा भंडारण उपकरणों का निर्माण और व्यापार, सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों और उत्पादों का आयात और निर्यात, सौर पैनल, चार्जर, पावर पैक व अन्य संबंधित उत्पादों का व्यापार और सौर ऊर्जा से जुड़े सभी व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होना है।

एमओएस यूटिलिटी लिमिटेड के सह-संस्थापक और कार्यकारी निदेशक तथा एमओएस लॉगकनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चिराग शाह ने साझेदारी के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय डाक के साथ यह रणनीतिक गठबंधन हमारी अच्छी व्यवस्था और प्रबंधन, उत्कृष्टता को महत्व देना और ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने का प्रमाण है। कंपनी ग्राहकों के लिए जरूरी डाक सेवाएं देकर अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने की उम्मीद करती है। इससे कंपनी की उद्योग में स्थिति मजबूत होगी और वह अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलेगी। 27 जुलाई, 2009 को 'एमओ एस यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल की गई। कंपनी अपने ऑनलाइन पोर्टल www.bizsolutionz.com के माध्यम से बी2बी, बी2बी2सी और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में डिजिटल प्रोडक्ट और सेवा देती है। यह प्लेटफ़ॉर्म दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं, छात्रों, गृहिणियों और बीमा एजेंट्स को ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है, जिससे वे अपने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकते हैं। कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कि बैंकिंग, यात्रा, बीमा, उपयोगिता सेवाएं, मनोरंजन, फ्रैंचाइजी, और अन्य सेवाएं, जो इसके व्यापार को विविधता प्रदान करती हैं।कंपनी देशभर के 1,68,018 भागीदारों के भौतिक और डिजिटल चैनलों को मिलाकर भुगतान समाधान, रेमिटेंस, उपयोगिता, यात्रा और बीमा जैसे विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती है, जो इसके बड़े नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। कंपनी का एकीकृत मॉडल ग्राहकों के लिए एक सुगम और निर्बाध अनुभव प्रदान करता है, जहां वे बिना किसी परेशानी के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का राजस्व 193.09 करोड़ रुपए, एबिटा 17.85 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 12.13 करोड़ रुपए था।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जुलाई में शेयरों में 32,365 करोड़ रुपये का निवेश किया

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। नीतिगत सुधार जारी रहने की उम्मीद, सतत आर्थिक वृद्धि तथा कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों की वजह से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 32,365 करोड़ रुपये का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि, इस महीने के पहले दो कारोबारी सत्रों (1-2 अगस्त) को एफपीआई ने शेयरों से 1,027 करोड़ रुपये निकाले हैं। बजट में इक्विटी निवेश पर पूंजीगत लाभ कर में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से एफपीआई प्रवाह में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बाजारों से जुड़े घटनाक्रम अगस्त में एफपीआई की गतिविधियों का रुख तय करेंगे। डेजर्व के सह-संस्थापक वैभव पोरवाल ने कहा, ''अर्थव्यवस्था में सुस्ती तथा कमजोर रोजगार के आंकड़ों के बाद यह निश्चित है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कटौती कितनी होगी। अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती संभव है।'' डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जुलाई में शुद्ध रूप से शेयरों में 32,365 करोड़ रुपये डाले हैं। इससे पहले जून में राजनीतिक स्थिरता और बाजारों में तेज उछाल के बीच एफपीआई ने शेयरों में 26,565 करोड़ रुपये का निवेश किया था। एफपीआई ने चुनाव नतीजों को लेकर असमंजस के बीच मई में शेयरों से 25,586 करोड़ रुपये निकाले थे। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में निरंतर वृद्धि की चिंता के बीच अप्रैल में उन्होंने शेयरों से 8,700 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की थी। मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के एसोसिएट निदेशक - प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि एफपीआई का प्रवाह बढ़ने की वजह सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान देना, उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे और सतत आर्थिक वृद्धि है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा दिया है। वहीं चीन के वृद्धि दर के अनुमान में कमी की गई है। यह भी भारत के पक्ष में गया है। आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने जुलाई में शेयरों के अलावा ऋण या बॉन्ड बाजार में 22,363 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे इस साल अबतक बॉन्ड बाजार में उनका निवेश बढ़कर 94,628 करोड़ रुपये हो गया है।

INDEX		Above / Below	Conf.		Normal Target		On Trending times.		
				T1	T2	T3	T4	T5	T6
NIFTY Spot	For BUY Above	24,758	24,782	24,802	24,822	24,850	24,868	24,926	24,991
	For SELL Below	24,678	24,654	24,633	24,613	24,585	24,568	24,509	24,444
Bk.Nifty Spot	For BUY Above	51,417	51,458	51,491	51,525	51,572	51,601	51,699	51,807
	For SELL Below	51,284	51,243	51,209	51,176	51,128	51,100	51,001	50,893

Data based on previous day closing

Source: VAISHALI KALA

क्लासिक लीजेंड्स हर साल 200 जावा-येजदी शोरूम खोलेगी

बिजनेस रेमेडीज/चेन्नई। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी तथा भारत में जावा और येजदी मोटरसाइकिलों की खुदरा विक्रेता कंपनी क्लासिक लीजेंड्स हर साल 200 खुदरा शोरूम खोलेगी। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष सिंह जोशी ने माउंट पूनमल्ली में 6,000 वर्ग फुट में फैले नए आउटलेट 'स्वास्तिक मोटर्स' का उद्घाटन करने के बाद कहा कि क्लासिक लीजेंड्स 15 अगस्त को मोटरसाइकिलों की लोकप्रिय बीएसए श्रृंखला को भी पेश करने की तैयारी कर रही है। इस शोरूम को देश का सबसे बड़ा शोरूम बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'वर्तमान में हमारे पास लगभग 450 डीलरशिप हैं। हमने चालू वित्त वर्ष तक इसे 600 तक ले जाने की योजना बनाई है। यदि आप इसकी तुलना किसी और से करें, तो हमें अभी भी बहुत आगे जाना है। अगले कुछ वर्षों तक हम हर साल 200 से ज़्यादा शोरूम जोड़ते रहेंगे।' शहर में सबसे बड़ा शोरूम स्थापित करने के बारे में उन्होंने कहा, 'हम चेन्नई में देश के सबसे बड़े जावा येजदी डीलरशिप के दरवाजे खोलने के लिए उत्साहित हैं। तमिलनाडु हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।' एक सवाल के जवाब में जोशी ने कहा, 'अभी हमारे ग्राहकों की औसत आयु 21 से 32 वर्ष के बीच है। हमारे 80 प्रतिशत ग्राहक या अधिकांश ग्राहक इसी आयु वर्ग के हैं। हमारी जावा 42, जावा 42 बॉबर, जावा 350 (बाजार में) बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एडवेंचर लगातार बिक रही है। रोडस्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है।' उन्होंने कहा कि कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम कर रही है और चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयार होने पर इसे घरेलू बाजार में उतारा जाएगा।

गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स ने ई-स्कूटर 'इब्लू फियो एक्स' का नया संस्करण उतारा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माता गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स ने

अपने ई-स्कूटर 'इब्लू फियो एक्स' का नया संस्करण पेश किया है। यह भारत में कंपनी का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खंड में दूसरा उत्पाद है। इसे 'भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो' 2024 में पहली बार पेश किया गया था। कंपनी की विज्ञप्ति के मुताबिक, इस ई-स्कूटर में 2.36 किलोवाट की बैटरी लगी है। यह एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 110 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसमें सीट के नीचे 28 लीटर 'स्टोरेज स्पेस' दी गई है। कंपनी ने इसकी शोरूम कीमत 99,999 रुपये तय की है। यह तीन साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है।

प्राकृतिक रबड़ की कमी से जुलाई में कुछ संयंत्रों में टायर उत्पादन 10 प्रतिशत गिरा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। वाहन टायर बनाने वाली कंपनियों के संगठन एटीएमए ने कहा कि प्राकृतिक रबड़ की कमी से जुलाई में देश के कुछ टायर संयंत्रों में उत्पादन 10 प्रतिशत घट गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरेलू प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता में गिरावट आई है। इसका असर टायर विनिर्माण पर भी देखने को मिल रहा है।

एटीएमए ने बयान में कहा कि जून, 2024 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 60,000 टन रहने का अनुमान था लेकिन इसकी वास्तविक उपलब्धता लगभग 30,000 टन ही रही।संगठन के महानिदेशक राजीव बुधराजा ने कहा, ''प्राकृतिक रबड़ की कमी से हमारी सदस्य कंपनियों के कुछ टायर संयंत्रों में जुलाई में उत्पादन 10 प्रतिशत से ज्यादा घट गया। उत्पादन योजना पूरी तरह से अव्यवस्थित है।'' उन्होंने कहा, ''केवल दो बंदरगाहों पर मंगाए जा सकने वाले आयातित रबड़ को एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र में ले जाया जा रहा है, ताकि संयंत्रों को चालू रखा जा सके, क्योंकि टायर एक सतत प्रक्रिया वाला उद्योग है।'' बुधराजा ने कहा कि प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता के अभाव में संयंत्र-स्तरीय विनिर्माण दांव पर है। कच्चे माल की चिंताएं टायर विनिर्माण में बाधा डाल सकती है।

हीरो मोटोकॉर्प ने फिलिपीन में परिचालन किया शुरू

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने फिलिपीन में परिचालन शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह रणनीतिक विस्तार कंपनी की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें कहा गया, टेराफिरमा मोटर्स कॉर्पोरेशन (टीएमसी) कंपनी के उत्पादों तथा सेवाओं के अनन्य 'असेंबलर' और वितरक के रूप में काम करेगा। टीएमसी फिलिपीन के अग्रणी मोटर वाहन समूहों में से एक है तथा कोलंबियन ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है।

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) निरंजन गुप्ता ने कहा, ''फिलिपीन में परिचालन शुरू होने से हमारी समग्र वैश्विक उपस्थिति मजबूत होगी... कोलंबिया के समूह के भीतर एक प्रतिष्ठित इकाई टीएमसी के साथ साझेदारी कर हम इस महत्वपूर्ण बाजार में अपनी उपस्थिति को तेजी से स्थापित करने तथा विस्तारित करने के लिए तैयार हैं।'' इस 6,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले संयंत्र की वार्षिक क्षमता 1,50,000 इकाइयों से अधिक है। टीएमसी के चेयरमैन बिएनवेनिडो सैनविक्टोरेस सेंटोस ने कहा, ''हीरो मोटोकॉर्प की वैश्विक विशेषज्ञता को अपने स्थानीय ज्ञान के साथ मिलाकर हम बाजार में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का इरादा रखते हैं।''

बजाज ऑटो की जुलाई में बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 3,54,169 इकाई रही

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। बजाज ऑटो की जुलाई में निर्यात सहित कुल वाहन थोक बिक्री सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 3,54,169 इकाई रही। पुणे स्थित वाहन विनिर्माता ने जुलाई 2023 में 3,19,747 दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन बेचे थे। कंपनी बयान के अनुसार, पिछले महीने कुल घरेलू बिक्री (वाणिज्यिक वाहनों सहित) 18 प्रतिशत बढ़कर 2,10,997 इकाई हो गई, जुलाई 2023 में यह 1,79,263 इकाई थी।समीक्षाधीन महीने में कुल निर्यात दो प्रतिशत बढ़कर 1,43,172 इकाई हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,40,484 वाहन था।

भारत की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति फिलहाल जेएलआर के लिए उपयुक्त नहीं: टाटा मोटर्स

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने कहा कि उसकी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की भारत की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लाभ उठाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि यह कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आयात शुल्क में रियायत दी जाती है।

इस वर्ष मार्च में सरकार ने टेस्ला जैसी प्रमुख वैश्विक ईवी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नई ईवी नीति की घोषणा की थी। इसके तहत उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए 35,000 डॉलर और उससे अधिक कीमत वाले वाहनों पर 15 प्रतिशत के कम सीमा शुल्क/आयात शुल्क दर पर सीमित संख्या में कारों का आयात करने की अनुमति दी गई। टाटा मोटर्स के समूह मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) पी बी बालाजी ने तिमाही आंकड़ों की घोषणा करते हुए कहा, 'इस समय वह विशिष्ट नीति हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, हमारा फिलहाल इसका लाभ उठाने का इरादा नहीं है।' वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जेएलआर की देश में भविष्य में ईवी के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर नजर रखते हुए भारत की नई ईवी नीति का लाभ उठाने की कोई योजना है। बालाजी ने कहा कि वर्तमान में भारत में जेएलआर का कारोबार बहुत अच्छी स्थिति में है, तथा बहुत मजबूती से बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, 'हमने अभी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट के विनिर्माण का स्थानीयकरण किया है, और हम इस मोर्चे पर ऑर्डर में भारी वृद्धि देख रहे हैं। जैसे-जैसे मात्रा बढ़ती है, हम यथासंभव स्थानीयकरण जारी रखना चाहेंगे, और यदि नीतिगत माहौल का हम लाभ उठाने में सक्षम होते हैं, तो हम निश्चित रूप से इसपर विचार करेंगे।'

विविध

जड़ी-बूटी दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में एक लाख पौधों का निशुल्क वितरण एवं वृक्षारोपण किया गया

देशभर में तहसील स्तर पर 2000 से अधिक स्थानों पर वृक्षारोपण व जड़ी-बूटी वितरण

एक हजार से अधिक लोगों ने किया रक्त दान

स्वामी रामदेव रामदेव ने लॉन्च किया वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का पोर्टल

शल्य तंत्र पर आधारित त्रिदिवसीय सम्मेलन की स्मारिका 'सुश्रुतकोण' का किया गया विमोचन

280 लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण तथा निःशुल्क चश्मों का वितरण

412 लोगों का निःशुल्क दंत परीक्षण तथा निःशुल्क डेंटल किट वितरण

बिजनेस रेमेडीज/हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस पतंजलि वैलनेस, पतंजलि योगपीठ-2 के योगभवन सभागार में जड़ी-बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के साथ-साथ पूरे देश में स्थापित पतंजलि योग समितियों के माध्यम से एक लाख से अधिक औषधीय पौधों यथा- नीम, तुलसी, एलोवेरा, लौंग तुलसी, आंवला आदि का निःशुल्क वितरण तथा रोपण किया गया। यह आयोजन पखवाड़े में मनाया गया जिसमे कल आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में पतंजलि सन्यासाश्रम के संन्यासियों ने माला गांव में जाकर हजारों पौधों का रोपण किया। साथ ही आचार्य बालकृष्ण के साथ हरिद्वार में 887 यूनिट तथा पूरे देश में स्थापित पतंजलि योग समितियों के माध्यम से एक हजार से अधिक यूनिट रक्त दान किया गया।

आचार्य बालकृष्ण का जीवन कर्ममय, पुरुषार्थमय व परमार्थमय : स्वामी रामदेव

जड़ी-बूटी दिवस के अवसर पर स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने उपस्थित जनसमूह को स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र व स्वस्थ विश्व के लिए वृक्षारोपण हेतु संकल्पित कराया। स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने वृक्षारोपण तथा आचार्य बालकृष्ण ने स्वयं रक्त दान कर जनसामान्य को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आचार्य बालकृष्ण का जीवन कर्ममय, पुरुषार्थमय व परमार्थमय है। पूर्वजों से प्राप्त अपने सनातन, सांस्कृतिक शाश्वत तत्वों को जीवन में आत्मसात कर जगत के कल्याण के लिए पूज्य आचार्य ने 50 वर्षों से अधिक तप एवं पुरुषार्थ किया है जो हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

जन्मदिवस तो मात्र बहाना है, निरंतर राष्ट्रसेवा के कार्य करते हुए, पेड़-पौधे लगाना हमारा लक्ष्य : आचार्य बालकृष्ण

इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जन्मदिवस तो मात्र बहाना है, निरंतर राष्ट्रसेवा के कार्य करते हुए, पेड़-पौधे लगाना हमारा लक्ष्य है। हमारी दृष्टि में जन्मदिवस हमारे पूरे साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने तथा भविष्य के लिए चिंतन-मनन करने का दिन है।

कार्यक्रम में स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का पोर्टल लॉन्च किया। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस पोर्टल में लगभग 7500 पादप वंश, लगभग 50 हजार से अधिक पादप प्रजातियाँ, 2000 से अधिक भाषाओं (संस्कृत भाषा के नामों सहित), 12 लाख स्थानीय नामों संस्कृत भाषा सहित, 2.5 लाख पर्यायवाची, 6.5 लाख यूनिक रेफरेंस कोड को एक साथ सूत्रबद्ध किया गया है। साथ ही पोर्टल में 10 से अधिक वनस्पति विज्ञान आधारित औषधीय प्रणाली, 964 उपचार पद्धति, 2000 से अधिक स्थानीय समुदायों तथा 2.5 लाख फॉल्क फॉर्मेशन की जानकारी को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि आज ही पतंजलि विश्वविद्यालय में शल्य तंत्र आधारित तीन दिवसीय सम्मेलन 'सुश्रुतकोण' का उद्घाटन किया जा रहा है। उपस्थित जनसमूह एवं स्वास्थ्य साधकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आयुर्वेद की शल्य परम्परा को पतंजलि के माध्यम से नई ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत शल्य की पूरी प्रक्रिया को आमजन आधुनिक तकनीक के माध्यम से लाईव देख सकेंगे। इस अवसर पर शल्य तंत्र पर आधारित त्रिदिवसीय सम्मेलन की स्मारिका 'सुश्रुतकोण' का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार में 887 यूनिट के साथ पूरे देश में स्थापित पतंजलि योग समितियों के माध्यम से हजारों यूनिट रक्त दान किया गया।

साथ ही हरिद्वार में 280 लोगों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण, 412 लोगों की निःशुल्क दंत चिकित्सा व निःशुल्क डेंटल किट वितरण, व्यापक स्तर पर औषधीय पौधों का वितरण व वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस अवसर पर लाखों औषधीय पौधों यथा- नीम, तुलसी, एलोवेरा, लौंग तुलसी, आंवला आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ से सम्बद्ध सभी प्रकल्पों तथा शिक्षण संस्थानों के संन्यासी, अधिकारी, कर्मयोगी, शिक्षकगण तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

भारत में बढ़ती हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य समस्या पर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञ ने बचाव एवं उपचार पर दी जानकारी

बिज़नेस रेमेडीज/जयपुर

भारत में हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो-आर्थराइटिस और रेह्यूमेटॉयड (गठिया) जैसी स्थितियां आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही हैं। भारत में हर साल 4 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बोन और जोड़ दिवस, मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों (हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतकों को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ) के बढ़ते प्रभाव के बारे में समाज को संवेदनशील बनाने और रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने का एक अवसर है। भारत में मस्कुलोस्केलेटल बीमारी पर सीओपीसीओआरडी अध्ययन के अनुसार, गठिया 15 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है, यानी 210 मिलियन से अधिक लोगो को। हड्डियों से संबंधित विकारों का प्रचलन मधुमेह, एड्स और कैंसर जैसी अन्य गैर-संचारी बीमारियों की तुलना में अधिक है। भारत में मस्कुलोस्केलेटल शिकायतों का अनुमानित प्रचलन 25 से 30

डॉ. अमित शर्मा
सीनियर कंसल्टेंट रुमेटोलॉजी
फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर

प्रतिशत के बीच है। रुमेटी गठिया की व्यापकता लगभग 0.4 प्रतिशत है, और घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग 3.34 प्रतिशत है।

मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के बारे में बात करते हुए, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट रुमेटोलॉजी डॉ. अमित शर्मा ने कहा, कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो-आर्थराइटिस और गठिया जैसे मस्कुलोस्केलेटल विकार हमारी आबादी को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, और उनके जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर रहे हैं। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और हानिकारक आदतों से बचने जैसी व्यापक गतिविधियों के माध्यम से रोकथाम को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इन स्थितियों का जल्दी पता लगाने और प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच भी महत्वपूर्ण है। इन उपायों को अपनाकर, हम अपने समुदाय में हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं।

हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए सुझाव :

1. मांसपेशियों की मजबूती और हाइड्रेशन : मांसपेशियों के निर्माण और जोड़ों को सहारा देने के लिए नियमित व्यायाम को शामिल करें। जोड़ों की चिकनाई और समग्र शारीरिक कार्य को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना महत्वपूर्ण है।

2. पोस्चर और गतिविधि प्रबंधन: रीढ़ और जोड़ों पर तनाव को कम करने के लिए दैनिक गतिविधियों के दौरान अच्छी मुद्रा का अभ्यास करें। अनावश्यक तनाव और संभावित चोटों से बचने के लिए उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को सीमित करें।

3. जॉइंट प्रोटेक्शन तकनीक : दैनिक कार्यों के दौरान जोड़ों पर तनाव को कम करने के लिए एर्गोनोमिक उपकरणों का उपयोग करें और सपोर्टिव जूते पहनें।

4.तनाव प्रबंधन: माइंडफुलनेस या योग जैसी तनाव कम करने वाली गतिविधियों में शामिल हों, क्योंकि पुराना तनाव मस्कुलोस्केलेटल दर्द को बढ़ा सकता है।

प्रकाशक एवं मुद्रक पुनीत जैन द्वारा सिंघवी पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए आकाशदीप प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स सेक्टर नं.11, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर-302020 जयपुर से मुद्रित एवं 217, सैकंड फ्लोर, ओके प्लस स्क्वायर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर से प्रकाशित। संपादक : पुनीत जैन मो. 9929106227, आर.एन.आई नं.: RAJHIN/2013/54166· पोस्टल रजि. नं. जयपुर सिटी/006/2024-26, E-Mail: remediesbusiness@gmail.com